द शूटर

सूरजपुर जिले से प्रकाशित प्रथम हिन्दी दैनिक

प्रधान संपादक- रूपेश दुबे: 9826169678
संपादक- प्रवीण दुबे: 9165083700

वर्ष-14 अंक-167 | प्रतापपुर, जिला- सूरजपुर छ.ग. से प्रकाशित | मंगलवार 04 अगस्त 2026 | पृष्ठ-8 | मूल्य- 2 रूपये

6 करोड़ की सड़क या हादसों का रास्ता, निर्माण में लापरवाही से बढ़ी ग्रामीणों की चिंता

*** सूचना बोर्ड गायब, सुरक्षा इंतजाम नदारद, गुणवत्ता पर गंभीर सवाल; ग्रामीण बोले, क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है पीडब्ल्यूडी**

ओड़गी, 03 अगस्त 2026
द शूटर।

किसी भी क्षेत्र का विकास तभी सार्थक माना जाता है, जब उससे लोगों का जीवन आसान और सुरक्षित बने। लेकिन यदि विकास कार्य ही लोगों के लिए खतरे का कारण बनने लगे, तो यह केवल निर्माण एजेंसी ही नहीं बल्कि निगरानी व्यवस्था की भी गंभीर विफलता मानी जाती है। ओड़गी विकासखंड से लगभग 30 किलोमीटर दूर चेंद्रा, डांडमोरनी और पकनी को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर इन दिनों कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं।लोक निर्माण विभाग द्वारा करीब 6 करोड़ रुपये की लागत से सड़क एवं पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है। वर्षों से जर्जर इस सड़क के बनने से हजारों ग्रामीणों को बेहतर आवागमन की उम्मीद जगी थी, लेकिन निर्माण कार्य में कथित लापरवाही, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवालों ने लोगों की उम्मीदों को चिंता में बदल दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सुधार नहीं किया गया तो यह सड़क सुविधा से ज्यादा हादसों का कारण बन सकती है।

निर्माण स्थल पर नहीं लगा सूचना बोर्ड, पारदर्शिता पर उठे सवाल

सरकारी निर्माण कार्यों में परियोजना का सूचना बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य होता है, ताकि आम नागरिकों को यह जानकारी मिल सके कि निर्माण एजेंसी कौन है, कार्य की लागत कितनी है, निर्माण अवधि क्या है और गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसकी है। लेकिन इस निर्माण स्थल पर कहीं भी सूचना बोर्ड दिखाई नहीं देता। ग्रामीणों का कहना है कि बिना सूचना बोर्ड के करोड़ों रुपये का कार्य कराया जाना पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उनका आरोप है कि जिले में कई निर्माण कार्य इसी तरह बिना आवश्यक जानकारी सार्वजनिक किए कराए जा रहे हैं।

पुलिया के पास खुला गड्ढा, हर पल बना रहता है हादसे का डर

निमार्णाधीन पुलिया के समीप गहरी खुदाई कर उसे खुला छोड़ दिया गया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि वहां न बैरिकेडिंग की गई है, न चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं और न ही रात में रिफ्लेक्टर या संकेतक लगाए गए हैं। इससे दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों के साथ-साथ स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और पैदल राहगीरों की जान जोखिम में बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय इस मार्ग से गुजरने वाला कोई भी व्यक्ति अनजाने में दुर्घटना का शिकार हो सकता है।

करोड़ों की परियोजना, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था शून्य

ग्रामीणों का कहना है कि जब सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है तो सबसे पहले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। लेकिन मौके पर सुरक्षा के न्यूनतम मानकों तक का पालन नहीं किया जा रहा। इससे लोगों में नाराजगी है और वे सवाल उठा रहे हैं कि आखिर विभाग और निर्माण एजेंसी किसकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा?

बारिश में जलभराव, धूप निकलते ही उड़ने लगती है धूल

निमार्णाधीन सड़क पर कई स्थानों पर बारिश का पानी जमा हो जाता है, जिससे वाहन फिसलने का खतरा बना रहता है। वहीं बारिश रुकते ही सड़क पर बिछी मिट्टी और गिट्टी से धूल के बादल उठने लगते हैं। इससे राहगीरों, स्कूली बच्चों, किसानों और आसपास के ग्रामीणों को रोजाना भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि निर्माण एजेंसी द्वारा नियमित पानी का छिड़काव भी नहीं कराया जा रहा।

निर्माण गुणवत्ता पर भी उठ रहे हैं गंभीर सवाल

ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि जहां निर्धारित मानकों के अनुसार डब्ल्यूबीएम किया जाना चाहिए था, वहां केवल मिट्टी डालकर उसके ऊपर जीरा गिट्टी बिछा दी गई। पर्याप्त पानी का छिड़काव और रोलर से दबाव भी नहीं किया गया। लोगों को आशंका है कि पहली ही तेज बारिश में सड़क उखड़ सकती है और करोड़ों रुपये की यह परियोजना कुछ ही समय में गड्ढों में तब्दील हो सकती है।

हर दिन खतरे के बीच सफर करने को मजबूर हैं ग्रामीण

यह मार्ग चेंद्रा, डांडमोरनी और पकनी सहित कई गांवों की जीवनरेखा है। प्रतिदिन इसी सड़क से छात्र-छात्राएं स्कूल जाते हैं, किसान अपनी उपज लेकर बाजार पहुंचते हैं, मरीज अस्पताल जाते हैं और ग्रामीण रोजमर्रा के कामों के लिए आवागमन करते हैं। ऐसे में निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने से हर दिन लोगों को जोखिम उठाकर सफर करना पड़ रहा है।

मंत्री की पहल से मिली थी सड़क की सौगात

यह सड़क लंबे समय से क्षेत्र की प्रमुख मांग रही थी। क्षेत्रवासियों की मांग पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की पहल से इस सड़क निर्माण को स्वीकृति मिली थी। लोगों को उम्मीद थी कि वर्षों पुरानी समस्या का समाधान होगा और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। लेकिन अब निर्माण कार्य में सामने आ रही कथित अनियमितताओं ने लोगों की उम्मीदों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि निर्माण गुणवत्ता से समझौता हुआ तो सरकार की मंशा और जनप्रतिनिधियों के प्रयास भी सवालों के घेरे में आ जाएंगे।

ग्रामीणों ने उठाई ये प्रमुख मांगें

ग्रामीणों ने प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से मांग की है कि निर्माण स्थल पर तत्काल बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड और रात्रिकालीन संकेतक लगाए जाएं। सभी निर्माण कार्यों में अनिवार्य रूप से सूचना बोर्ड स्थापित किए जाएं। जलभराव वाले हिस्सों का तत्काल सुधार कराया जाए। सड़क निर्माण की स्वतंत्र तकनीकी गुणवत्ता जांच कराई जाए। मानकों के विपरीत किए गए कार्यों को हटाकर दोबारा गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराया जाए। साथ ही लापरवाही बरतने वाली निर्माण एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जाए।

ग्रामीणों का सवाल, क्या हादसे के बाद खुलेगी विभाग की आंखें

करीब 6 करोड़ रुपये की इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीणों को सुरक्षित और बेहतर सड़क सुविधा देना था। लेकिन यदि निर्माण के दौरान ही सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही है, सूचना बोर्ड तक नहीं लगाए गए हैं और गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो यह केवल एक निर्माण कार्य का मामला नहीं बल्कि सरकारी जवाबदेही की भी परीक्षा है। अब देखना यह होगा कि लोक निर्माण विभाग समय रहते इन शिकायतों को गंभीरता से लेकर सुधारात्मक कदम उठाता है या फिर किसी बड़ी दुर्घटना के बाद कार्रवाई की औपचारिकता निभाई जाएगी। फिलहाल चेंद्रा, डांडमोरनी और पकनी के ग्रामीण इसी सवाल के साथ सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

अंडरएज ड्राइविंग पर सरगुजा पुलिस सख्त, स्कूल पहुंचकर विद्यार्थियों को किया जागरूक

*** नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर शुरू हुआ विशेष अभियान, अभिभावकों से भी की गई जिम्मेदारी निभाने की अपील**

अम्बिकापुर, 03 अगस्त 2026, द शूटर। सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाओं और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरगुजा पुलिस ने जिलेभर के स्कूलों में विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी देने के साथ यह समझाया जा रहा है कि बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि उनके जीवन के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है।डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा आईपीएस राजेश अग्रवाल के निर्देशन में यातायात पुलिस की टीम सोमवार को विक्टोरिया पब्लिक स्कूल पहुंची। यहां विद्यार्थियों को एकत्रित कर सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों के पालन और अंडरएज ड्राइविंग से होने वाले संभावित हादसों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने बच्चों से कहा कि वे स्वयं वाहन चलाकर स्कूल आने से बचें और केवल अधिकृत स्कूल वाहन अथवा अपने परिजनों के साथ ही विद्यालय का आवागमन करें।अभियान के तहत जिले के सभी विद्यालयों के प्राचार्यों और प्रधान पाठकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी छात्र-छात्रा को दोपहिया वाहन से स्कूल आने की अनुमति न दी जाए। यदि कोई विद्यार्थी ऐसा करते हुए पाया जाता है तो पहले उसे समझाइश दी जाएगी तथा उसके अभिभावकों को बुलाकर काउंसलिंग की जाएगी।पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जागरूकता और सुधारात्मक प्रयासों के बावजूद यदि नियमों की अनदेखी जारी रहती है तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई के साथ अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।

सरगुजा पुलिस का कहना है कि यह अभियान केवल स्कूलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यापक जनजागरूकता के माध्यम से अभिभावकों को भी लगातार जागरूक किया जाएगा। पुलिस ने सभी माता-पिता से अपील की है कि वे अपने नाबालिग बच्चों को किसी भी परिस्थिति में वाहन चलाने के लिए न दें और सड़क सुरक्षा नियमों का स्वयं भी पालन करें। आने वाले दिनों में जिले के विभिन्न विद्यालयों में यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

11 अगस्त को विश्रामपुर में होगा बालक आवासीय वॉलीबॉल अकादमी का चयन ट्रायल

*** 10 से 15 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ी ले सकेंगे भाग**

सूरजपुर, 03 अगस्त 2026, द शूटर।

जिला प्रशासन एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा विश्रामपुर में संचालित होने वाली बालक आवासीय वॉलीबॉल अकादमी के लिए 11 अगस्त को सुबह 11 बजे स्वामी आत्मानंद हिन्दी माध्यम विद्यालय, विश्रामपुर में चयन ट्रायल आयोजित किया जाएगा। ट्रायल में जिले के 10 से 15 वर्ष आयु वर्ग के इच्छुक बालक खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। चयनित खिलाड़ियों को आवासीय अकादमी में प्रशिक्षण देकर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा।ट्रायल में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को जन्मतिथि संबंधी मूल दस्तावेज साथ लाना होगा। अधिक जानकारी के लिए राजनाथ गुप्ता से 8770996414 पर संपर्क किया जा सकता है।

श्रावण के प्रथम सोमवार पर भोड़ियाबाबा धाम में उमड़ा आस्था का जनसैलाब

*** ऊंची पहाड़ी पर स्थित प्राचीन शिवधाम में दिनभर गूंजता रहा 'हर-हर महादेव', जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, भजन-कीर्तन और विशाल खीर भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने लिया प्रसाद**

ओड़गी, 03 अगस्त 2026, द शूटर। श्रावण मास का पहला सोमवार ओड़गी के प्राचीन भोड़ियाबाबा धाम में आस्था, विश्वास और शिवभक्ति के अद्भुत उत्सव के रूप में मनाया गया। सुबह की पहली किरण के साथ ही ऊंची पहाड़ी पर बसे इस प्राचीन शिव मंदिर की ओर श्रद्धालुओं के कदम बढ़ने लगे। दिन चढ़ने के साथ मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से भर गया और देर शाम तक हर-हर महादेव तथा बम-बम भोले के जयघोष पूरे क्षेत्र में गूंजते रहे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा क्षेत्र शिवमय हो उठा हो।ओड़गी सहित आसपास के दर्जनों गांवों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और जलाभिषेक कर अपने परिवार की सुख-समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की कामना की। श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और पंचामृत से विधिवत रुद्राभिषेक किया। बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प और फलों का अर्पण कर भक्तों ने पूरे श्रद्धाभाव से भोलेनाथ की आराधना की।

भक्ति, सेवा और समर्पण का अद्भुत संगम

मंदिर परिसर में पूरे दिन विशेष पूजा-अर्चना, रुद्राभिषेक, भजन-कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों का सिलसिला चलता रहा। महिला, पुरुष, बुजुर्ग, युवा और बच्चों सहित हर आयु वर्ग के श्रद्धालु भगवान शिव की भक्ति में लीन दिखाई दिए। पहाड़ी मार्ग पर लगी लंबी कतारें इस बात की गवाही दे रही थीं कि भोड़ियाबाबा धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि क्षेत्रवासियों की गहरी आस्था का केंद्र है।

विशाल खीर भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद

श्रावण सोमवार के पावन अवसर पर भोड़ियाबाबा के प्रथम भजन गायक परमेश्वर राजवाड़े एवं श्रद्धालुओं के सहयोग से विशाल खीर भंडारे का आयोजन किया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर स्वयं को धन्य महसूस किया। प्रसाद वितरण, स्वच्छता और व्यवस्थाओं में विकास समिति के सदस्यों तथा स्थानीय ग्रामीणों ने पूरे सेवा भाव के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाईं।

विकास समिति ने बताया आस्था का प्रमुख केंद्र

भोड़ियाबाबा विकास समिति के अध्यक्ष दानी पाण्डेय ने बताया कि यह धाम वर्षों पुराना धार्मिक स्थल है और श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक एवं दर्शन के लिए पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि यह मंदिर ओड़गी और आसपास के गांवों के लोगों की अटूट आस्था का प्रतीक है। समिति द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा, पेयजल, स्वच्छता और भंडारे की समुचित व्यवस्था की गई, वहीं मंदिर के समग्र विकास के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

आस्था जो हर वर्ष और गहरी होती जा रही है

भोड़ियाबाबा धाम में उमड़ी श्रद्धा की यह भीड़ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही उस आस्था का जीवंत प्रमाण थी, जो लोगों को हर वर्ष इस पवित्र पहाड़ी तक खींच लाती है। स्थानीय मान्यता है कि श्रावण मास में यहां सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की आराधना करने वालों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही विश्वास हर वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ा रहा है और भोड़ियाबाबा धाम को पूरे क्षेत्र की आध्यात्मिक पहचान बना रहा है।

रोक्तिमा यादव ने उद्योग, ग्रामोद्योग, कौशल विकास और श्रम विभाग की योजनाओं की समीक्षा

अधिकारियों को दो टूक निर्देश–योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने में बरतें गंभीरता

*** कलेक्टर बोलीं– योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन आम लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति मजबूत करने में अहम**

बैकुण्ठपुर।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने उद्योग, हथकरघा, ग्रामोद्योग, कौशल विकास तथा श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की गहन समीक्षा की। उन्होंने विभागवार योजनाओं की प्रगति, लक्ष्य, हितग्राहियों को मिल रहे लाभ तथा लंबित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्रीमती यादव ने कहा कि शासन द्वारा आम नागरिकों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी सुनिश्चित होगा, जब विभागीय अधिकारी मैदानी स्तर पर सक्रियता से कार्य करते हुए पात्र हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी दें और उन्हें लाभ लेने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ-साथ प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने माह अगस्त में विभागवार तिथिवार समीक्षा बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने सभी अधिकारियों को अगली समीक्षा बैठक में योजनाओं की अद्यतन प्रगति, लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि और लंबित प्रकरणों की पूरी जानकारी के साथ उपस्थित होने को कहा।

लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों से 761 लोगों को मिला रोजगार

उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान महाप्रबंधक ने बताया कि जिले में 79 लघु एवं सूक्ष्म उद्योग संचालित हैं। इनमें लगभग 6059.92 लाख रुपये का पूंजी निवेश हुआ है तथा इन उद्योगों के माध्यम से 761 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2025-26 में 14 का लक्ष्य निर्धारित था। इसके अंतर्गत 132 लाख रुपये की राशि का वितरण किया गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत वर्ष 2025-26 में 57 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। विभाग द्वारा 80 आवेदन बैंकों को प्रेषित किए गए, जिनमें से 29 हितग्राहियों के ऋण स्वीकृत हुए तथा 10 हितग्राहियों को

ऋण वितरित किया गया है।

श्रमिकों के पंजीयन एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा

श्रम विभाग के अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में 53,993 तथा शहरी क्षेत्रों में 5,504 पंजीयन हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 9,906 तथा शहरी क्षेत्रों में 3,436 हितग्राहियों का पंजीयन कराया गया है।
बैठक में बताया गया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक सहायता के लिए शासन द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें मिनीमाता महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना तथा मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना प्रमुख हैं।
इन योजनाओं के माध्यम से महिला निर्माण श्रमिकों को मातृत्व एवं परिवार के पोषण के लिए आर्थिक सहायता, श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति एवं उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, बेटियों को शिक्षा एवं आत्मनिर्भरता के लिए सहायता तथा वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे श्रमिकों को आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। दुर्घटना में मृत्यु अथवा दिव्यांगता की स्थिति में श्रमिक के परिवार को आर्थिक सहायता का भी प्रावधान है।

कौशल विकास योजना के तहत 320 प्रशिक्षित एवं प्रशिक्षणरत

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना की समीक्षा में वर्ष 2025-26 के प्रशिक्षण की जानकारी प्रस्तुत की गई। विभाग द्वारा जल वितरण संचालक, असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन, असिस्टेंट मेसन, मशरूम ग्रोवर तथा लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर लेवल-3 जैसे पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
प्रस्तुत जानकारी के अनुसार कुल 420 के वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 120 प्रशिक्षित तथा 200 प्रशिक्षणरत, अर्थात 320 प्रशिक्षणार्थियों की प्रगति दर्ज की गई है। कलेक्टर ने शेष लक्ष्य को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

स्वरोजगार योजनाओं से युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने पर जोर

बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में संचालित योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगारों को विभिन्न व्यवसायों के लिए बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना के अंतर्गत अधिकतम 50 हजार रुपये अथवा स्वीकृत ऋण की 50 प्रतिशत राशि तक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।
वर्ष 2025-26 की समीक्षा में अंत्योदय स्वरोजगार योजना के तहत 37 के लक्ष्य के विरुद्ध 35 प्रकरण प्रेषित तथा 34 प्रकरण स्वीकृत किए गए। इसी प्रकार आदिवासी स्वरोजगार योजना के तहत 21 प्रकरण प्रेषित तथा 18 प्रकरण स्वीकृत हुए। पीएम-अजय योजना के तहत भी प्रकरणों की प्रगति की जानकारी बैठक में प्रस्तुत की गई।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अंत्योदय स्वरोजगार योजना, आदिवासी स्वरोजगार योजना तथा पीएम-अजय योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने वर्तमान स्थिति और लंबित प्रकरणों की जानकारी कलेक्टर के समक्ष रखी।
कलेक्टर श्रीमती यादव ने कहा कि स्वरोजगार एवं कौशल विकास से जुड़ी योजनाएं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने अधिकारियों को पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें योजनाओं से जोड़ने तथा बैंक स्तर पर लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रभावी समन्वय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब उनका लाभ अंतिम पंक्ति के पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए विभागीय अधिकारी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें।
कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव ने हथकरघा तथा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा उचित जानकारी नहीं देने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि शासन की योजनाओं के बारे में उन्हें पूरी तरह जानकारी हो और पात्र हितग्राहियों को उनका लाभ मिले, इस पर विशेष ध्यान दें।

स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी: मेंड्राकला में नि:शुल्क आयुष स्वास्थ्य शिविर, सैकड़ों ग्रामीणों ने कराया परीक्षण

अम्बिकापुर, 03 अगस्त 2026, द शूटर। गांवों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने और लोगों को आयुर्वेद एवं आयुष चिकित्सा पद्धति के प्रति जागरूक बनाने की दिशा में ग्राम पंचायत मेंड्राकला में आयोजित नि:शुल्क आयुष स्वास्थ्य शिविर ग्रामीणों के लिए बेहद उपयोगी साबित हुआ। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे, जहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा आवश्यक परामर्श के साथ नि:शुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया।छत्तीसगढ़ जन जागृति सेवा समिति, जिला सरगुजा द्वारा संचालित स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के अंतर्गत जिला आयुष अधिकारी, अम्बिकापुर के सहयोग से ग्राम पंचायत मेंड्राकला स्थित शारदा स्कूल के पीछे जागृति भवन में शिविर आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य शासन की आयुष एवं आयुर्वेद संबंधी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाना तथा लोगों को पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के लाभ से परिचित कराना था।शिविर में पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराकर चिकित्सकों से अपनी समस्याओं पर सलाह ली और आवश्यक औषधियां प्राप्त कीं। चिकित्सकों ने मौसमी बीमारियों से बचाव, संतुलित जीवनशैली, योग तथा आयुर्वेदिक उपचार के महत्व पर भी विस्तार से जानकारी दी।छत्तीसगढ़ जन जागृति सेवा समिति की प्रदेश अध्यक्ष प्रभा यादव ने क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में शिविर का लाभ लेने की अपील की थी। शिविर की सफलता पर उन्होंने सभी चिकित्सकों, जनप्रतिनिधियों, आयुष विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, समिति के पदाधिकारियों तथा सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया।शिविर में आयुष विभाग की ओर से डॉ. लंकेश्वर सिंह (आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी), डॉ. विनय गुप्ता (आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी), डॉ. आदित्य गुप्ता (ग्रेजुएट आयुर्वेद), डॉ. तरूण राही (योग चिकित्सक), डॉ. अनीस अहमद मंसूरी (होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी), श्रीमती लकड़ा एवं अनुप तिर्की (फार्मासिस्ट), देव प्रसाद एवं सुरेन्द्र कुजूर (औषधालय सेवक), तथा चन्द्र प्रताप सिंह (एमपीडब्ल्यू) सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मियों ने अपनी सेवाएं प्रदान कीं। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, समिति के पदाधिकारियों एवं ग्रामीणों की भी उल्लेखनीय सहभागिता रही।ग्रामीणों का कहना था कि ऐसे स्वास्थ्य शिविर न केवल उपचार उपलब्ध कराते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी प्रभावी माध्यम बनते हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में इस तरह की पहल लोगों के लिए किसी राहत से कम नहीं है।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और साढ़े छह लाख की ठगी, आरोपी पुलिस गिरफ्त में

*** महिला संबंधी अपराध में मणीपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई, न्यायालय में पेश कर भेजा गया जेल**

अम्बिकापुर, 03 अगस्त 2026, द शूटर। शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने और उससे साढ़े छह लाख रुपये लेने के मामले में मणीपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। महिला संबंधी गंभीर अपराधों में त्वरित कार्रवाई के तहत पुलिस ने लगातार प्रयास कर आरोपी को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया।पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता ने थाना पुरानी बस्ती, रायपुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि 24 अप्रैल 2026 से 3 जुलाई 2026 के बीच बलौदाबाजार जिले के कसडोल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छाछी निवासी परमेश्वर साहू ने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने पीड़िता से 6 लाख 50 हजार रुपये भी ले लिए।मामले में थाना पुरानी बस्ती, रायपुर में प्रारंभिक रूप से शून्य पर अपराध दर्ज किया गया था। इसके बाद अग्रिम विवेचना के लिए प्रकरण थाना मणीपुर, अम्बिकापुर भेजा गया, जहां अपराध क्रमांक 137/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 एवं 351(3) के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़िता का विस्तृत बयान दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस टीम ने आरोपी परमेश्वर साहू (29 वर्ष), निवासी ग्राम छाछी, थाना कसडोल, जिला बलौदाबाजार को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने घटना से संबंधित तथ्य स्वीकार किए। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।इस कार्रवाई में थाना मणीपुर के थाना प्रभारी उप निरीक्षक सी.पी. तिवारी, महिला प्रधान आरक्षक मालती तिवारी सहित पुलिस टीम के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सक्रिय भूमिका रही। पुलिस ने कहा है कि महिला संबंधी अपराधों में दोषियों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार त्वरित और सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

श्रावण के प्रथम सोमवार पर शिवभक्ति में सराबोर दिखीं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, बीरपुर में कांवड़ यात्रा कर किया जलाभिषेक

सूरजपुर, 03 अगस्त 2026 द शूटर।
श्रावण मास के प्रथम सोमवार की अलौकिक बेला में पूरा बीरपुर गांव हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंज उठा। शिवभक्ति के इसी पावन वातावरण में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े भी एक सामान्य श्रद्धालु की तरह कांवड़ यात्रा में शामिल हुईं। आस्था, श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत इस यात्रा में उन्होंने भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा अर्पित करते हुए कंधों पर कांवड़ उठाई और पदयात्रा कर शिव मंदिर पहुंचीं।बीरपुर स्थित पासंग नाला से विधि-विधान के साथ पवित्र जल ग्रहण करने के बाद मंत्री श्रीमती राजवाड़े श्रद्धालुओं के साथ भजन-कीर्तन और बम-बम भोले के उद्घोष के बीच पैदल यात्रा करती हुईं मंदिर पहुंचीं। रास्ते भर शिवभक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो उठा था और हर कदम पर श्रद्धा की अनुभूति महसूस की जा रही थी।शिव मंदिर पहुंचकर मंत्री ने अपने परिवार के साथ भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक एवं विधिवत पूजा-अर्चना की। उन्होंने पूरे मनोभाव से देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हुए प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। साथ ही प्रार्थना की कि भगवान शिव की कृपा समस्त छत्तीसगढ़ पर सदैव बनी रहे तथा राज्य निरंतर विकास, शांति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर हो।इस अवसर पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि श्रावण मास केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि, आस्था और शिवभक्ति का महापर्व है। भगवान शिव की आराधना मनुष्य के भीतर सकारात्मक ऊर्जा, संयम, करुणा और लोककल्याण की भावना का संचार करती है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से प्रेम, सद्भाव और सेवा की भावना के साथ जीवन जीने का संदेश भी दिया। कुलमिलाकर श्रावण के प्रथम सोमवार पर बीरपुर में निकली यह कांवड़ यात्रा श्रद्धा और भक्ति का अनुपम संगम बन गई। शिवालय में गूंजते वैदिक मंत्र, श्रद्धालुओं के जयघोष और भोलेनाथ के चरणों में अर्पित आस्था ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। हर श्रद्धालु की आंखों में शिवभक्ति का भाव और मन में महादेव के प्रति अटूट विश्वास स्पष्ट दिखाई दे रहा था। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि समाज में एकता, सद्भाव और सनातन संस्कृति के प्रति लोगों की गहरी आस्था का भी प्रेरक संदेश दे गया।

नर्मदा उद्गम की गोद में सीख का नया अध्याय, अर्थशास्त्र विभाग के विद्यार्थियों ने किया अमरकंटक का शैक्षणिक भ्रमण

सूरजपुर, 03 अगस्त 2026, द शूटर। किताबों के पन्नों में दर्ज तथ्यों को जब प्रकृति, संस्कृति और समाज के बीच जाकर महसूस करने का अवसर मिलता है, तब शिक्षा केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि जीवन का अनुभव बन जाती है। इसी उद्देश्य को साकार करते हुए शासकीय रेवती रमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सूरजपुर के अर्थशास्त्र विभाग द्वारा छात्र-छात्राओं का शैक्षणिक भ्रमण मध्यप्रदेश के पवित्र तीर्थस्थल अमरकंटक स्थित नर्मदा उद्गम तक आयोजित किया गया।महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एच. एन. दुबे के निर्देशन तथा अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. रश्मि पाण्डेय एवं सहायक प्राध्यापक श्री आनंद कुमार पैकरा के मार्गदर्शन में आयोजित इस भ्रमण ने विद्यार्थियों को कक्षा की चारदीवारी से बाहर निकलकर

वास्तविक परिस्थितियों को समझने का अवसर प्रदान किया।भ्रमण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ व्यावहारिक अनुभवों से जोड़ना था, ताकि वे प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत तथा क्षेत्रीय विकास के विभिन्न पहलुओं का प्रत्यक्ष अध्ययन कर सकें। अमरकंटक पहुंचकर विद्यार्थियों ने नर्मदा उद्गम स्थल के धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को नजदीक से जाना। साथ ही स्थानीय सामाजिक जीवन, आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन से जुड़े विकास के आयामों का भी अध्ययन किया।इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. एच. एन. दुबे ने कहा कि शैक्षणिक भ्रमण विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे कार्यक्रमों से विद्यार्थियों में शोध की प्रवृत्ति, सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता और विश्लेषणात्मक सोच विकसित होती है। उन्होंने कहा कि पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान तब और अधिक सार्थक हो जाता है, जब उसे वास्तविक परिस्थितियों में परखा और समझा जाए। इससे विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और उनके व्यक्तित्व का भी समग्र विकास होता है।सहायक प्राध्यापक श्री आनंद कुमार पैकरा ने विद्यार्थियों को क्षेत्रीय अध्ययन की उपयोगिता, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास को समझने के लिए वहां की भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक होता है।भ्रमण के दौरान छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक विभिन्न स्थलों का अवलोकन किया, आवश्यक जानकारियां संकलित कीं और प्रकृति के संरक्षण का संदेश भी आत्मसात किया। विद्यार्थियों ने इस शैक्षणिक यात्रा को ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और जीवनभर याद रहने वाला अनुभव बताते हुए कहा कि इस तरह के भ्रमण उन्हें नई दृष्टि और व्यापक सोच प्रदान करते हैं।

जियो टावर के सुस्त नेटवर्क से परेशान उपभोक्ता, एक सप्ताह के बाद सामाजिक कार्यकर्ता देंगें धरना

प्रतापपुर/द शूटर। प्रतापपुर नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में जियो नेटवर्क की खराब गुणवत्ता को लेकर उपभोक्ताओं में लगातार नाराजगी बढ़ रही है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता मो. जीशान खान ने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जियो कंपनी की नेटवर्क व्यवस्था में तत्काल सुधार कराने की मांग की है।

ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले कई महीनों से जियो का नेटवर्क अत्यंत कमजोर है। कॉल बार-बार कट जाती है, इंटरनेट की गति बेहद धीमी रहती है तथा कई स्थानों पर नेटवर्क पूरी तरह गायब हो जाता है। इससे विद्यार्थियों, व्यापारियों, ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने वाले नागरिकों तथा आम उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से मांग की गई है कि एक सप्ताह के भीतर नेटवर्क व्यवस्था में सुधार कराया जाए। चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समय में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अगले सोमवार जियो टावर के पास शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित कंपनी और प्रशासन की होगी।
मो. जीशान खान ने कहा कि नागरिक लंबे समय से बेहतर नेटवर्क सेवा की मांग कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। अब उपभोक्ताओं के हित में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है।

रामानुजनगर से उठी पहल, अब पूरे जिले में संकुल समन्वयकों की मूल विद्यालयों में वापसी की बढ़ी उम्मीद

*** शासन के स्पष्ट नियमों के बाद समान कार्रवाई की मांग तेज, पालकों और शिक्षकों ने कहा, बच्चों की पढ़ाई से नहीं होना चाहिए समझौता**

सूरजपुर/ रामानुजनगर 03 अगस्त 2026, द शूटर। जिले के रामानुजनगर विकासखंड में संकुल समन्वयकों को उनके मूल विद्यालयों में वापस भेजे जाने के फैसले ने पूरे सूरजपुर जिले में शिक्षा व्यवस्था को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। लंबे समय से उठ रही मांग पर प्रशासनिक पहल होने के बाद अब अन्य विकासखंडों के शिक्षक, पालक और ग्रामीण भी ऐसी ही कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका कहना है कि यदि एक विकासखंड में नियमों के अनुरूप व्यवस्था लागू हो सकती है, तो बाकी क्षेत्रों में भी इसमें देरी का कोई औचित्य नहीं है।दरअसल, जिले के कई विद्यालयों में ऐसे शिक्षक वर्षों से संकुल समन्वयक के रूप में दूसरे स्थानों पर कार्य कर रहे हैं, जिनकी नियुक्ति किसी अन्य विद्यालय में है। इसका सीधा असर उन स्कूलों पर पड़ा, जहां पहले से शिक्षकों की कमी थी। कई जगह विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई से भी वंचित होना पड़ा और पालकों ने समय-समय पर इस स्थिति पर नाराजगी जताई।

शासन ने पहले ही तय कर दिए थे स्पष्ट नियम

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में संकुल समन्वयकों के चयन और उनकी जिम्मेदारियों को लेकर स्पष्ट व्यवस्था निर्धारित की गई है। नियमों के अनुसार एकल या द्वि-शिक्षकीय विद्यालयों से किसी शिक्षक को संकुल समन्वयक नहीं बनाया जाएगा। समन्वयक उसी संकुल की किसी शाला में पदस्थ होना चाहिए तथा चयन जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा और कलेक्टर व जिला मिशन संचालक (समग्र शिक्षा) की स्वीकृति के बाद ही किया जाएगा।

इतना ही नहीं, शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि संकुल समन्वयक अपनी मूल पदस्थ शाला में प्रतिदिन न्यूनतम तीन कालखंड अध्यापन करेंगे। इसके साथ ही वे शैक्षणिक गतिविधियों का समन्वय, लर्निंग आउटकम की निगरानी, शैक्षणिक कैलेंडर का पालन तथा विद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। ऐसे में शिक्षकों की अपने विद्यालयों में नियमित उपस्थिति शासन की मंशा का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा रही है।

पवनपुर में बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा था असर

पवनपुर का विद्यालय पहले से ही एकल शिक्षक व्यवस्था पर निर्भर था। इसके बावजूद वहां पदस्थ शिक्षक जयप्रकाश सिंह बंदोभवना संकुल में समन्वयक की जिम्मेदारी निभा रहे थे। इससे विद्यालय की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। अब उनके मूल विद्यालय लौटने से ग्रामीणों और अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। उनका मानना है कि अब बच्चों को नियमित पढ़ाई का लाभ मिलेगा।

लेडुवा और जगतपुर के विद्यालयों को भी मिलेगी मजबूती

माध्यमिक शाला लेडुवा में केवल तीन शिक्षक पदस्थ होने के बावजूद दो शिक्षकों को संकुल स्तर की जिम्मेदारी दी गई थी। इनमें रविशंकर पांडेय देवनगर संकुल में कार्यरत थे। उनकी वापसी से विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है।

इसी तरह माध्यमिक शाला जगतपुर के शिक्षक विनय चौरसिया लंबे समय से कौशलपुर संकुल में समन्वयक के रूप में कार्यरत थे। इस विषय को लेकर कई बार शिकायतें भी सामने आईं और मामला समाचारों की सुर्खियां बना। अब उनकी वापसी को स्थानीय लोगों ने शिक्षा व्यवस्था के हित में उठाया गया उचित कदम बताया है।

अन्य शिक्षकों की भी हुई मूल पदस्थापना

प्राथमिक शाला जगतपुर के सहायक शिक्षक राघवेन्द्र नाथ दुबे, जो भुवनेश्वरपुर संकुल में कार्यरत थे, तथा माध्यमिक शाला नर्मदापारा भुवनेश्वरपुर के प्रधान पाठक तेजपुर भी लंबे समय से संकुल समन्वयक की जिम्मेदारी निभा रहे थे। इनकी मूल विद्यालयों में वापसी को भी सकारात्मक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

अब पूरे जिले से उठ रही एक जैसी मांग

रामानुजनगर में हुई कार्रवाई के बाद अब जिले के अन्य विकासखंडों से भी आवाज उठने लगी है। पालकों का कहना है कि सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी संभव है, जब प्रत्येक शिक्षक अपने मूल विद्यालय में उपस्थित रहकर विद्यार्थियों को पूरा समय दे। यदि शासन ने स्पष्ट नियम बना दिए हैं, तो उनका पालन पूरे जिले में एक समान होना चाहिए।

पुराने मामलों की समीक्षा की भी उम्मीद

क्षेत्र में यह चर्चा भी है कि कुछ संकुलों में लंबे समय से प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती रही हैं। नए समन्वयकों के कार्यभार संभालने के बाद इन मामलों की निष्पक्ष समीक्षा होने की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि इन आरोपों की अब तक किसी सक्षम स्तर पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

अब जिला प्रशासन के फैसले का इंतजार

रामानुजनगर की पहल ने यह विश्वास जरूर जगाया है कि इच्छाशक्ति हो तो नियमों का पालन कर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है। अब पूरे सूरजपुर जिले के शिक्षक, पालक और ग्रामीणों की निगाहें जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग पर टिकी हैं। सभी की अपेक्षा है कि शेष विकासखंडों में भी शीघ्र ऐसी ही कार्रवाई कर शिक्षकों को उनके मूल विद्यालयों में पदस्थ किया जाएगा, ताकि हर स्कूल में बच्चों को पूरा शैक्षणिक वातावरण और नियमित अध्यापन उपलब्ध हो सके।

उम्मीदों के साथ पहुंचे लोग, समाधान का भरोसा लेकर लौटे, जनदर्शन में 45 आवेदनों पर कलेक्टर रेना जमील ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

सूरजपुर, 03 अगस्त 2026 द शूटर। सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में एक बार फिर जनदर्शन के दौरान आमजन की उम्मीदें और प्रशासन की जवाबदेही एक साथ दिखाई दी। जिले के गांवों से लेकर नगर निकाय क्षेत्र तक के लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने की आस लेकर पहुंचे। किसी ने वर्षों पुराने भूमि विवाद को लेकर गुहार लगाई, तो किसी ने पेंशन, बिजली, पेयजल और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परेशानियां प्रशासन के सामने रखीं। हर आवेदन केवल एक कागज नहीं, बल्कि उसके पीछे किसी परिवार की चिंता, संघर्ष और समाधान की उम्मीद साफ झलक रही थी।साप्ताहिक जनदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने कुल 45 आवेदन कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के समक्ष प्रस्तुत किए। प्राप्त आवेदनों में राजस्व, भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विद्युत, पेयजल, सड़क तथा अन्य विभागों से जुड़े अनेक प्रकरण शामिल रहे।जनदर्शन के दौरान कलेक्टर रेना जमील ने प्रत्येक आवेदक की बात गंभीरता से सुनी और सभी आवेदनों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए तत्काल प्रेषित किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी आवेदन को केवल औपचारिक प्रक्रिया मानकर फाइलों में सीमित न रखा जाए, बल्कि हर मामले का गंभीरता, संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ परीक्षण करते हुए निर्धारित समय-सीमा में उसका निराकरण सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि जनदर्शन प्रशासन और जनता के बीच विश्वास का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। यहां पहुंचने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस उम्मीद के साथ आता है कि उसकी बात सुनी जाएगी और समस्या का समाधान भी होगा। इसलिए पात्र प्रकरणों में अनावश्यक विलंब न हो, आवश्यक होने पर मौके पर जांच कर त्वरित कार्रवाई की जाए और आवेदकों को उनके प्रकरण की प्रगति से भी अवगत कराया जाए। उन्होंने दोहराया कि किसी भी नागरिक को अपनी समस्या के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की स्थिति नहीं बननी चाहिए।उन्होंने लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करने, विभागीय समन्वय बढ़ाने और हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी, संवेदनशील और परिणाममुखी प्रशासन ही लोगों का विश्वास मजबूत कर सकता है। प्रशासन की सफलता तभी मानी जाएगी, जब समस्याओं का समाधान समय पर लोगों तक पहुंचे और उन्हें वास्तविक राहत मिले। कुलमिलाकर जनदर्शन का यह आयोजन एक बार फिर इस बात का संदेश देकर समाप्त हुआ कि प्रशासन केवल शिकायतें सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि हर आवेदन के पीछे छिपी मानवीय पीड़ा और अपेक्षाओं को समझते हुए समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। यही संवेदनशील और जवाबदेह कार्यशैली सुशासन की पहचान है और आमजन के विश्वास की सबसे बड़ी आधारशिला भी।

योजनाओं की सफलता का पैमाना आंकड़े नहीं, आम लोगों तक पहुंचने वाला लाभ है : समय सीमा की बैठक में सीईओ ने अधिकारियों को दिया स्पष्ट संदेश

*** एग्री स्टैक, आयुष्मान, शिक्षा, पेयजल, आवास और कौशल विकास समेत सभी विभागों की प्रगति की हुई गहन समीक्षा**

सूरजपुर, 03 अगस्त 2026 द शूटर।सरकारी योजनाएं तभी अपने उद्देश्य को पूरा करती हैं, जब उनका लाभ बिना किसी बाधा के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। इसी सोच के साथ सोमवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजेन्द्र सिंह पाटले ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि योजनाओं की प्रगति केवल फाइलों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसका असर गांवों और लोगों के जीवन में दिखाई देना चाहिए। इसके लिए नियमित मैदानी निरीक्षण और सतत निगरानी बेहद जरूरी है। बैठक में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय निकाय, आवास, कौशल विकास सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। प्रत्येक विभाग के एजेंडा बिंदुओं पर अलग-अलग चर्चा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए।

ग्राम सभाओं में पढ़े जाएंगे छूटे किसानों के नाम

कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान सीईओ ने एग्री स्टैक पंजीयन की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन पात्र किसानों का अभी तक पंजीयन नहीं हो पाया है, उनके नाम ग्राम सभाओं में पढ़कर सुनाए जाएं, ताकि कोई भी किसान जानकारी के अभाव में इस प्रक्रिया से वंचित न रह जाए।बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सक्रिय हितग्राहियों में से अब तक 77 हजार 382 किसानों का फार्मर रजिस्ट्री में पंजीयन हो चुका है। शेष किसानों का ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और लैंड सीडिंग का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही किसानों को दलहन, तिलहन और उद्यानिकी फसलों की खेती के लिए प्रेरित करने तथा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत ऑयल पाम पौधरोपण अभियान में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया।

आयुष्मान कार्ड और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दिए स्पष्ट निर्देश

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में आयुष्मान कार्ड निर्माण की प्रगति पर संतोष जताया गया, लेकिन जिन पात्र लोगों के कार्ड अभी तक नहीं बने हैं, उनके कार्ड शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह की जांच, शत-प्रतिशत टीकाकरण तथा टीबी, मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए चल रहे अभियानों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों से कहा गया कि तय लक्ष्य समय पर पूरे किए जाएं।

बच्चों का आधार और आभा आईडी बनाने में नहीं हो ढिलाई

महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान बच्चों के आधार पंजीयन और आभा आईडी निर्माण की प्रगति पर चर्चा हुई। सीईओ ने निर्देश दिए कि प्रत्येक शुक्रवार ग्राम पंचायतों में लगाए जाने वाले आधार शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि कोई भी बच्चा इस सुविधा से वंचित न रहे।

विद्यालयों में पढ़ाई के साथ पोषण और हरियाली पर भी रहेगा जोर

स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, बुनियादी साक्षरता, पीएम पोषण योजना, सरस्वती साइकिल वितरण और पीएम श्री योजना की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई।

सीईओ ने निर्देश दिए कि जिले के सभी विद्यालयों में किचन गार्डन का शेष कार्य सितंबर के अंत तक पूरा किया जाए। उन्होंने समुदाय की भागीदारी से संचालित न्योता भोजन कार्यक्रम को भी निरंतर जारी रखने और इसे अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया।

हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने पर जोर

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा में जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत कार्यों की प्रगति पर चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे किए जाएं और प्रत्येक घर तक कार्यशील नल कनेक्शन के माध्यम से नियमित पेयजल उपलब्ध कराया जाए।

आवास, रोजगार और सौर ऊर्जा योजनाओं की भी हुई समीक्षा

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0, एसएलआरएम एवं एमआरएफ सेंटरों की प्रगति, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षण लक्ष्य तथा रोजगार मेलों के आयोजन की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को सभी योजनाओं में गति लाने और निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए।

लंबित प्रकरणों पर जताई नाराजगी

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत समय सीमा से अधिक लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए सीईओ ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसे मामलों का प्राथमिकता के आधार पर तत्काल निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।बैठक के अंत में जिला पंचायत सीईओ विजेन्द्र सिंह पाटले ने सभी विभाग प्रमुखों से योजनाओं की नियमित समीक्षा, मैदानी निरीक्षण और समयबद्ध कार्य संस्कृति अपनाने की अपील करते हुए कहा कि विकास की वास्तविक तस्वीर तभी बनेगी, जब योजनाओं का लाभ बिना देरी और बिना भेदभाव के हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे।बैठक में अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा, जिले के सभी एसडीएम तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

रेल की पटरियों पर पहुंचेगी उम्मीदों की सौगात, लाइफ लाइन एक्सप्रेस से हजारों जरूरतमंदों को मिलेगा नया जीवन

*** कलेक्टर रेना जमील ने विश्रामपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर तैयारियों का लिया जायजा, 16 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेगा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर**

सूरजपुर, 03 अगस्त 2026, द शूटर। अक्सर इलाज की कमी, आर्थिक तंगी या विशेषज्ञ चिकित्सकों तक पहुंच न होने के कारण कई लोग वर्षों तक बीमारी का दर्द अपने भीतर दबाए जीते रहते हैं। ऐसे ही जरूरतमंद लोगों के लिए इस बार विश्रामपुर रेलवे स्टेशन उम्मीदों का एक नया पड़ाव बनने जा रहा है। 16 अगस्त से जिले में पहुंचने वाली लाइफ लाइन एक्सप्रेस हजारों लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य और नई जिंदगी का संदेश लेकर आएगी।इसी की तैयारियों का जायजा लेने सोमवार को कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने विश्रामपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक-02 का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ पूरे परिसर का अवलोकन करते हुए मरीजों के पंजीयन, प्रतीक्षा कक्ष, पेयजल, साफ-सफाई, बैठक व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य आवश्यक सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाएं ताकि जिले के किसी भी मरीज को उपचार के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

कलेक्टर ने कहा कि यह केवल एक स्वास्थ्य शिविर नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए जीवन बदलने का अवसर है जो लंबे समय से गंभीर बीमारियों के बावजूद उपचार नहीं करा सके हैं। उन्होंने सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर अधिक से अधिक लोगों तक इस सुविधा को पहुंचाने पर जोर दिया।

16 अगस्त से 5 सितंबर तक मिलेगी विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा

लाइफ लाइन एक्सप्रेस विश्रामपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक-02 पर 16 अगस्त से 5 सितंबर 2026 तक प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक सेवाएं देगी। इस दौरान सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न रोगों की निःशुल्क जांच एवं चयनित मरीजों की सर्जरी की जाएगी।शिविर में आंखों की जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन, कान संबंधी जांच और सर्जरी, कटे-फटे होंठ तथा जलने के बाद होने वाले संकुचन की प्लास्टिक सर्जरी, दांतों की जांच एवं उपचार, महिलाओं के स्तन एवं गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर की स्क्रीनिंग तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मुड़े हुए हाथ-पैर की जांच एवं सर्जरी की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

तय कार्यक्रम के अनुसार होगी ओपीडी और सर्जरी

कार्यक्रम के अनुसार आंखों की ओपीडी 16 से 21 अगस्त तथा सर्जरी 17 से 22 अगस्त तक होगी। कान की ओपीडी 22 से 27 अगस्त और सर्जरी 23 से 28 अगस्त तक चलेगी। प्लास्टिक सर्जरी एवं मुड़े हुए हाथ-पैर की ओपीडी 28 से 31 अगस्त तथा सर्जरी 29 अगस्त से 1 सितंबर तक की जाएगी। वहीं दांतों का उपचार 1 से 5 सितंबर तक और महिलाओं के स्तन एवं सर्वाइकल कैंसर की जांच 16 से 21 अगस्त तक की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों से मरीजों की पहचान पर रहेगा विशेष जोर

जिला प्रशासन ने सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंच, मितानिन, सखी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं से अपील की है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ऐसे मरीजों की पहचान कर उनका समय पर पंजीयन कराएं और उन्हें शिविर तक पहुंचने के लिए प्रेरित करें। प्रशासन का उद्देश्य है कि आर्थिक या सामाजिक कारणों से इलाज से वंचित कोई भी जरूरतमंद इस अवसर से पीछे न रह जाए।शिविर में आने वाले मरीजों को आधार कार्ड, वोटर आईडी या अन्य वैध पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। भर्ती मरीज के साथ केवल एक सहायक को ही अनुमति दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 7039673973 पर संपर्क किया जा सकता है।

स्वास्थ्य सेवा आपके द्वार की पहल बनेगी नई उम्मीद

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक जरूरतमंद मरीज इस निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठाएं और अपने आसपास के लोगों को भी इसकी जानकारी दें। उन्होंने विश्वास जताया कि लाइफ लाइन एक्सप्रेस न केवल हजारों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करेगी, बल्कि स्वस्थ सूरजपुर, समृद्ध सूरजपुर के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। उनके अनुसार जब उपचार जरूरतमंदों के द्वार तक पहुंचे, तभी स्वास्थ्य सेवा का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है।

पर्यावरण मंज़ूरी पर सरकार को बरतनी होगी सावधानी

पर्यावरण मंज़ूरी पर जल्दबाजी नहीं, सरकार को सोच-समझकर उठाने होंगे कदम सुप्रीम कोर्ट के 'वनशक्ति' मामले में हालिया आदेश से पता चलता है कि कोर्ट ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की ऐसी व्याख्या की है जो सरकार को कुछ प्रोजेक्ट्स को बिना पहले से पर्यावरण मंज़ूरी के शुरू करने की इजाजत देने का अधिकार देती है। हालांकि, भारत के मुख्य न्यायाधीश (तत्कालीन) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने केंद्र सरकार द्वारा 2021 में जारी उस ऑफिस मेमोरेंडम को रद्द कर दिया, जिसके तहत बिना पहले से मंज़ूरी लिए प्रोजेक्ट्स को अनुमति देना संभव हो गया था, लेकिन कोर्ट ने एढ अधिनियम के तहत ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए एक सीमित कानूनी माफी योजना (स्टैच्यूटरी एमनेस्टी स्कीम) लाने की सरकार की शक्ति को बरकरार रखा। असल में, रउ ने उन पुराने फैसलों को ज्यादा अहमियत दी जिनमें काम शुरू होने के बाद मंज़ूरी (पोस्ट-फैक्टो क्लीयरेंस) देने की इजाजत थी, बजाय उन फैसलों के जिनमें नियमों का सख्ती से पालन करने और 2006 के पर्यावरण प्रभाव आकलन नियमों के तहत पहले से मंज़ूरी लेने को जरूरी माना गया था। सुरक्षा के लिहाज से, कोर्ट ने अपने आदेश को भविष्य के लिए लागू किया, और 2021 के ऑफिस मेमो और 2017 के नोटिफिकेशन के तहत अब तक मंजूर किए गए प्रोजेक्ट्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ दांव पर पर्यावरण की अखंडता और उन प्रोजेक्ट्स के लिए उसमें बदलाव करने की असली कीमत लगी है, जिनका अक्सर संसाधनों के दोहन, प्रदूषण और पारिस्थितिकी के नुकसान के मामले में बहुत बड़ा असर होता है। एढ अधिनियम की धारा 3 की यह व्याख्या करना कि सरकार को कानूनी नोटिफिकेशनों के जरिए काम शुरू होने के बाद पर्यावरण मंज़ूरी देने की शक्ति है, एक बहुत ही अनोखी सोच है, जबकि यह धारा केंद्र सरकार को केवल पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए उपाय करने की शक्ति देती है। अनिवार्य कर दिया पिछले साल 'वनशक्ति' मामले में रउ द्वारा तय किए गए सख्त एउ (पर्यावरण मंज़ूरी) नियमों के खिलाफ सरकार की दलीलों की वजह से कोर्ट को कुछ महीनों बाद अपना ही आदेश वापस लेना पड़ा। यह तर्क दिया गया था कि पोस्ट-फैक्टो एउ के बिना मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जैसी कीमती राष्ट्रीय संपत्तियाँ हाथ से निकल जाएँगी। सरकारी दावों में चुनिंदा बातों पर जोर देने से खदानों, हाईवे, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और औद्योगिक संयंत्रों के पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को नजरअंदाज कर दिया गया। जानिए इसके पीछे की प्रमुख वजहें किसी देश में जीवन की गुणवत्ता उसके पर्यावरण की स्थिति पर निर्भर करती है। जहाँ भौतिक बुनियादी ढाँचे और व्यावसायिक गतिविधियों में किए गए सभी निवेशों को विकास को बढ़ावा देने वाला माना जाता है, वहीं पर्यावरण को होने वाले नुकसान को अभी तक मुख्यधारा की ऋऊढ गणना में शामिल नहीं किया गया है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का कहना है कि ग्रीन ऋऊढ के अनुमान पर काम चल रहा है, हालांकि पिछली बार इस दिशा में कोई खास कोशिश 2013 में हुई थी। सबसे ज्यादा आबादी और इस्तेमाल लायक सीमित जमीन वाले देश के तौर पर, भारत को अपने पर्यावरण में बदलाव करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। राष्ट्रीय नीति में फैसले लेते समय लागत और फायदे का सही अनुमान लगाना जरूरी है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 (समानता और जीवन के अधिकार) और पीढ़ियों के बीच समानता के सिद्धांत के अनुरूप हो। ऐसी चिंताएं ही एढ एक्ट और 2006 के एकअ नोटिफि केशन का आधार हैं। 'पोस्ट-फैक्टो एउ' (काम शुरू होने के बाद मिलने वाली पर्यावरण मंज़ूरी) के लिए लंबित हर आवेदन को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और मंज़ूरी एक पारदर्शी, ऑडिट की गई प्रक्रिया के जरिए दी जानी चाहिए।

सरकार ने राष्ट्रगान से पहले 'वंदे मातरम' गाना अनिवार्य कर दिया

पहले 'वंदे मातरम' गाना अनिवार्य कर दिया नरेंद्र मोदी सरकार अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से तय करने के लिए तारीफ की हकदार है। ऐसे समय में जब बाकी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स को अपना रही है, भारत ने उस चुनौती से निपटने का फैसला किया है जिसने देश की नींद उड़ा रखी थीः उन लोगों का क्या किया जाए जो पूरा 'वंदे मातरम' ठीक से नहीं गा पाते? सरकार अब राष्ट्रीय गीत को भी राष्ट्रीय गान की तरह ही कानूनी सुरक्षा देने जा रही है। जानबूझकर बाधा डालने, रुकावट पैदा करने या अनादर करने पर तीन साल तक की जेल और जुमार्ना हो सकता है। बार-बार ऐसा करने वालों को सरकारी आवास में कम से कम एक साल रहने का मौका मिलेगा–बशर्ते हमारी पहले से ही खचाखच भरी जेलों में उनके लिए जगह हो। यह कानून तब आया है जब महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रमों में पहले 'वंदे मातरम' और बाद में 'जन गण मन' गाना अनिवार्य कर दिया गया है। भारत उन बहुत कम देशों में से एक बन सकता है जहाँ किसी भी कार्यक्रम की शुरूआत से पहले राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों को अनिवार्य रूप से गाना होगा। दोनों को मिलाकर चार मिनट से ज्यादा का समय लगता है, और इस दौरान हर किसी से–ऊजार्वान स्कूली बच्चों से लेकर बुजुर्गों और बीमार लोगों तक–सम्मानपूर्वक सावधान की मुद्रा में खड़े रहने की उम्मीद की जाती है। कि पिछले 75 वर्षों से गाए जा रहे 'वंदे मातरम' के छोटे संस्करण से काम नहीं चलेगा। अब बंकिम चंद्र चटर्जी की पूरी रचना गाई जानी चाहिए। हालाँकि, छोटी-मोटी राहत के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। रवींद्रनाथ टैगोर के 'जन गण मन' को पूरा गाने का आदेश अभी तक नहीं दिया गया है। अगर ऐसा होता, तो भारत न केवल सबसे लंबे चुनावी भाषणों के लिए, बल्कि आधिकारिक कार्यक्रमों से पहले सबसे लंबे अनिवार्य संगीत-परिचय के लिए भी रिकॉर्ड बुक में जगह बना सकता था। जानिए इसके पीछे की प्रमुख वजहें इस विडंबना को नजरअंदाज करना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फैसला सुनाया था कि किसी भी नागरिक को राष्ट्रीय गान गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह फैसला केरल के 'जेहोवा विटनेस' परिवार के तीन बच्चों के मामले में आया था, जो गान बजने के दौरान सम्मानपूर्वक खड़े तो रहते थे, लेकिन अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण उसे गाने से इनकार कर देते थे। कोर्ट ने सही कहा था कि सम्मान को जुबानी भागीदारी से नहीं मापा जा सकता और राज्य द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने के बाद उनके अधिकारों को बहाल किया था। हाउसिंग सोसायटियों में उनकी कानूनी भूमिकाओं को समझना एक और छोटी सी दिक्कत है।

गोल्ड ATM को लेकर उठे सवाल, सुविधा के साथ काले धन के इस्तेमाल की चिंता भी बढ़ी

सुविधा के साथ काले धन के इस्तेमाल की चिंता भी बढ़ी गोल्ड अळट लोगों को पारंपरिक शोरूम जाए बिना सर्टिफाइड फिजिकल गोल्ड कॉइन खरीदने या पुराने सोने के गहने बेचकर तुरंत कैश पाने की सुविधा देते हैं। ये क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके 24-कैरेट, 999-प्योरिटी वाले हॉलमार्क गोल्ड कॉइन (0.5 ग्राम से 100 ग्राम तक के वजन में) देते हैं। ये सोना बेचने में भी मदद करते हैं। कुछ एडवांस्ड मशीनें पुराने सोने के गहनों को वहीं एनालाइज करती हैं, उनका वजन करती हैं और उन्हें पिघलाकर उनकी कीमत के बराबर कैश तुरंत बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हैं। इनकी कीमत ग्लोबल बुलियन मार्केट की रियल-टाइम कीमतों के आधार पर तय होती है, इसलिए ग्राहकों को बिना किसी छिपी हुई मेकिंग या वेस्टेज फीस के पारदर्शी मार्केट रेट पर सोना मिलता है या बेचा जाता है। अ'२ङ्ग र्फी - पर्यावरण मंज़ूरी पर सरकार को बरतनी होगी सावधानी संयुक्त अरब अमीरात (वअए) को दुनिया का पहला गोल्ड अळट लगाने का श्रेय जाता है, जिसे मई 2010 में अबू धाबी के एमिरेट्स पैलेस होटल में शुरू किया गया था। अब वअए में नए फिनटेक-पावर्ड नेटवर्क फैल रहे हैं। अब ये दुनिया की ज्यादातर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मौजूद हैं। भारत में इसे दिसंबर 2022 में हैदराबाद के बेगमपेट में 'गोल्डसिक्का' ने 'ओपनक्यूब टेक्नोलॉजीज' के टेक सपोर्ट से लॉन्च किया था। इसे बहुत ज्यादा खरीदार नहीं मिले, हालांकि ऐसे अळट पर काफी संख्या में लोग आए जरूर हैं। , जो उन तीर्थयात्रियों की जरूरतें पूरी करता है जो भगवान के चरणों में सोने के सिक्के चढ़ाना चाहते हैं। भारत में गोल्ड अळट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, क्योंकि लोग पारंपरिक ज्वैलर्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं, सोना खरीदने में बड़ी रकम लगती है, और लोग मशीन से बिना किसी पर्सनल टच के कच्चे सिक्के खरीदने के बजाय ज्वैलर के पास जाकर गहने खरीदने का अनुभव पसंद करते हैं। भारतीय भरोसेमंद लोकल ज्वैलरी शॉप पर जाना पसंद करते हैं, जहाँ वे गहनों को देख-परख सकते हैं, मोल-भाव कर सकते हैं और लंबे समय के रिश्ते बना सकते हैं। सोना खरीदना एक सांस्कृतिक और भावनात्मक अनुभव है, जो अक्सर त्योहारों और पारिवारिक परंपराओं से जुड़ा होता है, और एक मशीन यह अनुभव नहीं दे सकती। अळट से ज्यादातर छोटे 24-कैरेट सिक्के या बार ही मिलते हैं, जबकि खरीदार अक्सर पहनने लायक गहने या भारी निवेश के लिए सोना चाहते हैं। ऐसे में, गोल्ड अळट ज्यादातर सोने के सिक्कों में निवेश करने वालों की ही जरूरतें पूरी कर सकते हैं। जानिए इसके पीछे की प्रमुख वजहें भारत में सोना और रियल एस्टेट काले धन को जमा करने की जगह के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। सरकार ने खास तौर पर इन दो जगहों पर कैश के इस्तेमाल को कम करने की कोशिश की है, लेकिन लिमिट के अंदर रहने के लिए खरीदारी को टुकड़ों में बांटने की आदत ने गोल्ड इकॉनमी को मुख्यधारा में लाने की सरकार की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शहरों और गांवों, दोनों ही जगहों पर सोने की बहुत मांग है। और गांवों में तो आज भी कैश का ही बोलबाला है। सोने की खरीदारी में सोने के गहनों का हिस्सा ज्यादा (करीब 55%) रहा है, जबकि निवेश के तौर पर खरीदे जाने वाले सोने के सिक्कों और बिस्कुट का हिस्सा करीब 45% रहा है। हाउसिंग सोसायटियों में उनकी कानूनी भूमिकाओं को समझना भारत में 30,000 टळ से 35,000 टळ सोना मौजूद है, जो मुख्य रूप से घरों और मंदिरों के पास है। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भी सुरक्षित एसेट के तौर पर सोना है। देश में सोने का उत्पादन बहुत पहले ही बंद हो चुका है, इसलिए सोने का आयात देश के कुल आयात में दूसरे नंबर पर आता है। युद्ध से जूझ रही दुनिया में विदेशी मुद्रा बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक साल तक सोना न खरीदने की अपील सही समय पर की गई थी, लेकिन गोल्ड अळट इसके उलट काम करते दिख रहे हैं। यह सरकार की उस कोशिश के भी खिलाफ है जिसमें निवेशकों को फिजिकल सोने से हटाकर म्यूचुअल फंड यूनिट्स के जरिए पेपर गोल्ड की ओर ले जाने की बात कही गई है। अगर पीछे मुड़कर देखें, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की पार्टी, 'तमिलगा वेट्री कझगम' (ळश्ङ) ने अपने चुनावी घोषणापत्र में सोने से जुड़े बड़े कल्याणकारी वादे किए थे, जिनमें शादी के लिए 8 ग्राम सोना और नवजात बच्चों के लिए सोने की अंगूठी देना शामिल था। सरकार की ऐसी योजनाएं देश पर आयात का बोझ बढ़ाती हैं। कल्याणकारी योजनाओं का मकसद फिजूलखर्ची नहीं होना चाहिए। इसके बजाय, ऐसी योजनाएं बनाई जानी चाहिए जो लोगों को अपने पास रखे बेकार सोने को बेचने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करें, शायद 'गोल्ड एमनेस्टी स्कीम' (सोने से जुड़ी माफी योजना) के जरिए। भारत अपनी सालाना घरेलू सोने की सप्लाई का लगभग 11% रीसायकल करता है। मेटल की बढ़ती कीमतों की वजह से 2026 की दूसरी तिमाही में यह आंकड़ा रिकॉर्ड 50.3 टन तक पहुंच गया। लेकिन सालों से जमा पड़े बेकार सोने के मुकाबले यह बहुत कम है। दुनिया भर में सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं,

लड़की की टिप्पणी नहीं, असली मुद्दे से ध्यान हटने पर बढ़ा आक्रोश

असली मुद्दा कुछ और था! लड़की की भाषा नहीं, ध्यान भटकाने वाली बात पर उठा विवाद एक प्रदर्शनकारी की अभद्र टिप्पणी पर हुए विवाद ने उस मुद्दे को पीछे छोड़ दिया, जिसके लिए सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे थे। ध्यान का यह बदलाव उन शब्दों से कहीं ज्यादा गौर करने लायक है। क्या किसी प्रदर्शनकारी की अभद्र भाषा राष्ट्रीय आपातकाल का मुद्दा बन सकती है? आज देश ठीक इसी सवाल से जूझ रहा है। और यह सब हुआ एक खुद को टीनएजर बताने वाली लड़की, एक छात्र विरोध प्रदर्शन में उसकी असंसदीय भाषा, प्रधानमंत्री की नरमी भरी नसीहत और देश से ₹गुमराह युवाओं को सही राह दिखाने₹ की अपील के कुछ ही घंटों बाद सामने आए उसके माफी वाले वीडियो की वजह से। एक प्रदर्शनकारी की अभद्र भाषा को प्रधानमंत्री की गरिमा से जुड़े राष्ट्रीय मुद्दे में बदलने में छह दिन लग गए, लेकिन विरोध प्रदर्शन के असली मकसद को भुलाने में जरा भी समय नहीं लगा। तो, कहानी के उस लड़की के हाथ से निकलने से पहले असल में क्या हुआ था, आइए जानते हैं। 23 जुलाई को जंतर-मंतर पर उखढ के विरोध प्रदर्शन के दौरान, नोएडा के एक सैलून में काम करने वाली 25 साल की रुचिका सिंह ने कैमरे पर प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे। यह वीडियो वायरल हो गया। छह दिन बाद, भारतीय न्याय संहिता (इठर) की धाराओं 352, 353(1) और 356(1) के तहत सार्वजनिक अपमान, सार्वजनिक उपद्रव और मानहानि के लिए उसके खिलाफ कथित तौर पर जीरो ऋक्षफ़ दर्ज की गई। खबर है कि वह भूमिगत हो गई है। रिपोर्टर उसके पुराने सैलून के बाहर डेरा डाले हुए हैं और उसके पुराने साथियों से ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जैसे उसने कोई हिंसक अपराध किया हो। मैं उस भाषा का बचाव नहीं कर रहा हूँ। असल में, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। वे शब्द भद्दे और अपमानजनक थे, और ठीक वैसी ही बातें थीं जो पहले से ही बंटी हुई सार्वजनिक बहस को और भी बदतर बना देती हैं। मैं उन शब्दों में से एक का भी बचाव नहीं करूँगा। हालाँकि, जो सवाल मुझे हैरान करता है, वह यह हैः आखिर देश को क्या नुकसान हुआ? किसी को चोट नहीं पहुँची, किसी संपत्ति को नुकसान नहीं हुआ। एक महिला ने भीड़ के सामने कुछ भद्दी बात कही, भीड़ ने तालियाँ बजाईं और वीडियो फैल गया। बस यही अपराध था। यह असभ्य है, सार्वजनिक बहस की गरिमा के खिलाफ है और साफ तौर पर भारत गणराज्य के लिए कोई खतरा नहीं है। इसे सार्वजनिक उपद्रव, मानहानि और आरोपी की तलाश जैसे मामलों की तरह देखना, जंतर-मंतर पर असल में क्या हुआ था, इसके बजाय यह ज्यादा बताता है कि इस कहानी को कौन कंट्रोल कर रहा है। फिर रुचिका का माफी मांगने वाला वीडियो भी है। हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए एक लड़की या महिला का वीडियो सामने आया झ यह लड़की है या महिला, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे पूछ रहे हैं, क्योंकि 15 साल₹ की उम्र का एकमात्र सोर्स वही क्लिप है, जिसकी कभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई। वह पूरे देश से माफी मांग रही थी। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, वह अपने आस-पास की भीड़ के असर में थी और उसने माफी मांगी। यह वीडियो प्रधानमंत्री के उस वीडियो के कुछ ही घंटों बाद सामने आया जिसमें उन्होंने ₹गुमराह बच्चों₹ को माफ कर दिया था। हो सकता है कि यह महज एक इत्तेफाक हो, लेकिन यह ऐसा लगता नहीं है। ऋक्षफ़ डॉक्सिंग (निजी जानकारी सार्वजनिक करने) और मीडिया की घेराबंदी के डर से रिकॉर्ड की गई माफी असल में कोई कबूलनामा नहीं है। यह बेहतर लाइटिंग वाला एक 'बंधक का वीडियो' (ँङ्ग२३ॅ ३स्त्री) जैसा है। जानिए इसके पीछे की प्रमुख वजहें लेकिन मुझे जो बात परेशान करती है, वह उसके शब्द नहीं हैं। बल्कि उसके बाद आई वह प्रतिक्रिया है जो बड़प्पन या उदारता के तौर पर पेश की गई। प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया उस वीडियो के रूप में आई जिसे कई लोगों ने कल्चरल शॉक (सांस्कृतिक झटका) वाला वीडियो बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को माफ कर दिया है, और याद दिलाया कि न सिर्फ. उन्हें, बल्कि उनकी दिवंगत माँ को भी अपशब्द कहे गए थे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इन गुमराह बच्चों को सही रास्ते पर वापस लाएँ। यह एक ऐसे घायल लेकिन उदार दादाजी जैसी छवि का जबरदस्त चित्रण था, जो कई भारतीय परिवारों में आम है। फिर भी, देश के नेता को कोई सीधा नुकसान नहीं पहुँचा था। न तो उन्हें और न ही उनके दफ़्तर को शारीरिक रूप से कोई खतरा था। हफ़्तों तक, न्यूज में परीक्षा का पेपर लीक होने और छात्रों की मौत को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों की ही चर्चा रही थी। फिर कहानी का रुख बदल गया। हेडलाइंस और प्राइम-टाइम डिबेट्स में विरोध प्रदर्शन के बजाय, एक दयालु नेता की छवि पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा जो एक युवा प्रदर्शनकारी की आपत्तिजनक बातों को माफ कर रहा है। इस बदलाव पर ध्यान देना जरूरी है। विरोध प्रदर्शन से जुड़े असहज सवालों से ध्यान हटाकर प्रधानमंत्री की उदारता पर बात करना ज्यादा आसान है। उन सवालों में यह भी शामिल था कि क्लिप सामने आने से पहले के दिनों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों (जिनमें नाबालिग भी शामिल थे) को हिरासत में क्यों लिया था। एक कहानी संस्थागत शक्ति के बारे में असहज सवाल उठाती है; दूसरी कहानी एक महिला के आपत्तिजनक शब्दों पर केंद्रित है।

व्यापार का छोटा रास्ता, बड़े रणनीतिक बदलाव का संकेत

बड़े रणनीतिक बदलाव का संकेत भारत और चीन के बीच छह साल के अविश्वास को सिर्फ.एक दर्रे (स्त्र२२) के फिर से खुलने से खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन यह उस पुल की पहली कड़ी हो सकती है जो दोनों देशों के बीच की दूरी को कम कर सके। 1 अगस्त को, छह साल से ज्यादा समय की खामोशी के बाद, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले 14,140 फीट ऊंचे हिमालयी दर्रे 'नाथू ला' पर बर्फीले 'नो-मैन्स-लैंड' (दोनों देशों के बीच की खाली जमीन) के आर-पार व्यापार फिर से शुरू हुआ। भारतीय और चीनी अधिकारियों की मौजूदगी में व्यापारियों ने ऊन, रेशम, कंबल और बोरेक्स का आदान-प्रदान किया – यह एक छोटा सा व्यापारिक कार्यक्रम था, लेकिन इसका कूटनीतिक महत्व बहुत बड़ा था। इसमें शामिल आंकड़े बहुत कम हैंः अपने आखिरी पूरे साल में इस दर्रे से मुश्किल से 49 करोड़ रुपये का सामान गुजरा, जो 150 अरब डॉलर के करीब के द्विपक्षीय व्यापार के मुकाबले न के बराबर है। फिर भी, शायद ही दुनिया में किसी और बॉर्डर क्रॉसिंग पर याक की ऊन के हर किलोग्राम के साथ इतना इतिहास जुड़ा हो। नाथू ला की कहानी खुद दोनों देशों के रिश्तों की तरह हैः पहले अच्छे संबंध, फिर टूटे, और फिर सावधानी से सुधारे गए। 1962 की लड़ाई के बाद यह दर्रा बंद हो गया और चार दशकों से ज्यादा समय तक बंद रहा; यह 2006 में प्रधानमंत्री वाजपेयी के समय शुरू हुई 'विशेष प्रतिनिधियों' की सीमा वार्ता के कुछ ठोस नतीजों में से एक के तौर पर फिर से खुला। यह सुधार 2020 तक चला, जब लगभग एक साथ दो घटनाएं हुईंः कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया भर में सीमाएं बंद हो गईं, और लद्दाख में 'लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल' (छअउ) पर चीनी सेना ने आक्रामक रुख अपनाया। उस साल जून में गलवान घाटी में हुई झड़प – जो 45 सालों में भारत और चीन के बीच सबसे घातक टकराव था – में भारतीय और चीनी सैनिक मारे गए, हालांकि मारे गए भारतीय सैनिकों की संख्या कहीं ज्यादा थी। महामारी के बावजूद, नाथू ला के जरिए होने वाला व्यापार, पर्यटन और कैलाश मानसरोवर की तीर्थयात्रा सब रुक गए। परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसियों के बीच नाराजगी या कड़वाहट को छह साल तक बनाए रखना एक लंबा समय है। लद्दाख के सबसे विवादित इलाकों से सेना हटाने की प्रक्रिया महामारी के बाद भी काफी समय तक खिंचती रही, और असली तेजी तब आई जब अक्टूबर 2024 में कजान में ब्रिक्स (इफक्कर) शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। इसके बाद धीरे-धीरे प्रगति हुईः पिछले अगस्त में दिल्ली में विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता का 24वां दौर हुआ, सात साल में मोदी की चीन की पहली यात्रा (तियानजिन में रउड शिखर सम्मेलन के लिए) हुई, और एक साझा, बिना कही गई प्रेरणा भी काम कर रही थी

युवाओं के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन इतने सफल क्यों रहे? जानिए इसके पीछे की प्रमुख वजहें

नेपाल में हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण पिछले कुछ हफ़्तों में भारत में कुछ बदला है। लंबे समय तक, ज्यादातर लोगों के लिए इखढ के नेतृत्व वाली ठऊअ सरकार और उसके नेताओं की आलोचना करना बहुत मुश्किल, या लगभग नामुमकिन जैसा था। लेकिन 'कॉकरोच जनता पार्टी' (उखढ) के विरोध-प्रदर्शनों ने इसे ऐसे मुमकिन बना दिया जिसकी कई लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही यह मुमकिन हुआ, विरोध की बाढ़ आ गई। नेशनल एग्जाम के पेपर लीक होने से रोकने में सरकार की बार-बार की नाकामी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन, लोकतांत्रिक असहमति की एक ऐसी स्थायी तस्वीर बन गए, जिसमें उन मुद्दों पर भी बात होने लगी जिन पर लोग पहले बात करने से डरते थे। इस मायने में, उखढ के विरोध-प्रदर्शनों ने वह कर दिखाया जो विपक्षी पार्टियाँ 12 साल से ज्यादा समय से नहीं कर पाई थींः सरकार को सत्ता के अहंकार से नीचे उतरने पर मजबूर करना। उखढ के आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। भले ही यह आंदोलन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और छात्रों की दूसरी अहम माँगों को सरकार द्वारा मान लिए जाने के साथ खत्म हो गया हो, लेकिन इस आंदोलन ने सिर्फ. पेपर लीक को लेकर निराशा ही नहीं दिखाई, बल्कि शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ व्यापक शिकायतों, बढ़ते भ्रष्टाचार के आरोपों, युवाओं में रिकॉर्ड बेरोजगारी, जवाबदेही की कमी और लोकतांत्रिक संस्थाओं में घटते भरोसे जैसी बड़ी चिंताओं को भी सामने रखा। सरकार ने पहले के विरोध-प्रदर्शनों को नजरअंदाज करने, बदनाम करने और ध्यान भटकाने की जो चालें चली थीं, वे इस बार काम नहीं आईं; न ही पुलिस की हिंसा से इसे दबाने की कोशिश सफल रही। अपनी ताकत दिखाने की जो रणनीति रही है–जिसमें कभी पीछे न हटना, कभी सफाई न देना और अपनी बात को एक खास तरह से पेश करना शामिल है–वह शायद पहले सफल रही हो, लेकिन इस बार विरोध कर रहे युवाओं के पक्के इरादे ने सरकार को उनकी माँगें मानने पर मजबूर कर दिया। सरकार ने छात्रों की माँगें तभी मानीं जब उसे एहसास हुआ कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। अगर एक स्तर पर ये विरोध-प्रदर्शन एग्जाम और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के बारे में थे, तो साथ ही ये सरकार के फैसलों और कामों के लिए जवाबदेही, सुशासन, आजादी, राजनीतिक नैतिकता, लोकतांत्रिक अधिकारों और भारत के भविष्य के बारे में भी थे–एक ऐसा भविष्य जिसे वे सभी के लिए अच्छी शिक्षा और अच्छे रोजगार के मौकों के रूप में देखते हैं। शायद इस विरोध प्रदर्शन की सबसे खास बात उखढ की वह काबिलियत थी, जिससे उसने संसद के बाहर राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष की भूमिका निभाई। उसने खराब शिक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों के गुस्से को एक बड़े आंदोलन में बदल दिया, जिसका मुख्य चेहरा बार-बार होने वाले पेपर लीक थे, जबकि इसके पीछे सरकार के खिलाफ कई मुद्दों और आम आदमी की समस्याओं को लेकर फैली नाराजगी थी। इस नजरिए से देखें तो ये विरोध प्रदर्शन सरकार के साथ-साथ विपक्ष की भी आलोचना के तौर पर देखे जा सकते हैं; विपक्ष जो बंटा हुआ है, जिसके पास संसाधनों की कमी है और जो ताकतवर सरकार को चुनौती देने में नाकाम रहा है।

यह कहना गलत नहीं होगा कि सत्ताधारी दल की ताकत यानी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, उखढ ने सरकार के नैरेटिव का सीधे मुकाबला किया और अपने विरोध प्रदर्शन के लिए बड़े पैमाने पर समर्थन जुटाकर राजनीतिक खालीपन को भरा। अनिवार्य कर दिया नाराजगी और गुस्से के साथ-साथ कुछ और समस्याएं भी हैं, जैसे असमान आर्थिक विकास, क्रोनी कैपिटलिज्म (खास उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली व्यवस्था) और अक की वजह से रोजगार के मौकों पर पड़ रहा असर। सरकार के खिलाफ बढ़ती नाराजगी (एंटी-इनकंबेंसी) भी उतनी ही अहम है, क्योंकि सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के आधे रास्ते पर है। जिस सरकार ने देश को बदलने का वादा किया था, उसके बावजूद भारतीय अभी भी सर्वांगीण विकास, बेहतर जीवन-स्तर और भ्रष्टाचार-मुक्त शासन के वादों से बहुत दूर हैं। वादे और उन्हें पूरा करने के बीच का अंतर काफी बड़ा है और यह जीवन के हर पहलू में दिखता है। सरकार की प्रचार मशीनरी ने मौजूदा नेतृत्व के तहत भारत के अभूतपूर्व बदलाव का दावा करने वाले नैरेटिव और अभियानों के जरिए इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। अ'२ङ्ग र्फी - चेयरमैन या सेक्रेटरी? हाउसिंग सोसायटियों में उनकी कानूनी भूमिकाओं को समझना अगर सोचें तो, भारत जैसे गरीब लेकिन विकासशील देश में, हर युवा नागरिक के लिए - खासकर मध्यम वर्ग के युवाओं के लिए - शिक्षा आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक तरक्की का मुख्य जरिया है। शिक्षा की खराब गुणवत्ता और परीक्षाओं में गड़बड़ी छात्रों से उनके हालात सुधारने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एकमात्र मौका छीन लेती है। लेकिन जब आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की उस प्रक्रिया में हेरफेर किया जाता है, जो लोगों और हाशिए पर पड़े समूहों को अधिकार, अवसर और संसाधन दिलाती है, तो अन्याय की भावना महत्वाकांक्षी आबादी के एक बड़े हिस्से में फैल जाती है - चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या वर्ग के हों।

शोएब अख़्तर को शाहरुख खान से मायूसी क्यों हुई, आसिफ जरदारी और अल्ताफ हुसैन से उन्होंने क्यों संपर्क किया था?

फास्ट बॉलर शोएब अख़्तर के बारे में बात करने से पहले उन्हें सही तरीके से समझना जरूरी है.यह मामला इतना आसान नहीं है. अलग-अलग लोग उन्हें अलग नजरिए से देखते रहे हैं. इसी वजह से उनकी शख़्सियत की अलग-अलग तस्वीर सामने आती रही है. कुछ लोगों के लिए वह ऐसे बॉलर थे जो अपनी रफ़्तार से बल्लेबाजों को परेशान कर देते थे. वहीं, कई लोग उन्हें एक अक्खड़ मिजाज और बागी क्रिकेटर मानते थे, जो अनुशासन की परवाह नहीं करते थे.उनके आलोचक अक्सर विवादों की एक लंबी सूची गिना देते थे. इसमें संदिग्ध बॉलिंग एक्शन, बॉल टैंपरिंग और डोपिंग के आरोप शामिल थे.उन पर प्रतिबंध भी लगे. जुर्माने भी हुए. उन्हें कई जांच समितियों और अदालतों के सामने भी पेश होना पड़ा. अनुशासन के उल्लंघन के मामले तो पूरे करियर में उनका पीछा करते रहे.लेकिन सच यह है कि शोएब अख़्तर का करियर किसी सुपरहिट फिल्म की तरह रहा. उसमें वह सब कुछ था जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचे रखे.

उन्हें क्रिकेट से संन्यास लिए 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं. अब वह अक्सर टीवी पर विश्लेषक के तौर पर दिखाई देते हैं. उनके बयान आज भी उतने ही तेज और धारदार होते हैं जितनी उनकी गेंदबाजी हुआ करती थी.अपनी किताब कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स में शोएब लिखते हैं कि बचपन में उन्हें बहुत तेज खांसी की बीमारी हो गई थी. इसकी वजह से वह कमजोर होते जा रहे थे. डॉक्टरों ने कहा था कि उनके फेफड़े हमेशा कमजोर रहेंगे. शोएब के मुताबिक, एक दिन उनके नाना ने उनकी मां से कहा कि यह बच्चा शायद ज़िंदा नहीं बचेगा. इसलिए इसके इलाज पर समय और पैसे बर्बाद मत करो. लेकिन उनकी मां ने हार नहीं मानी. वह लगातार उन्हें अस्पताल ले जाती रहीं.शोएब लिखते हैं कि बाद में उन्हीं फेफड़ों में इतनी ताकत आ गई कि वह मैदान में हवा की तरह दौड़ने लगे.

जब शोएब ने क्रिकेट को गंभीरता से लेना शुरू किया तो वह मौकों की तलाश में शहर-शहर जाने लगे. एक बार उन्हें पता चला कि पीआईए टीम के ट्रायल लाहौर में हो रहे हैं. वह अपने दोस्त एजाज अरशद के साथ रावलपिंडी से रवाना हो गए. उनकी जेब में सिर्फ 12 रुपये थे और दोस्त के पास 13 रुपये.शोएब बताते हैं कि सात घंटे का सफर बिना टिकट बस में तय किया. लाहौर पहुंचने के बाद होटल में रुकने के पैसे भी नहीं थे.

रेलवे स्टेशन के पास उनकी मुलाकात एक तांगे वाले अजीज खान से हुई. शोएब ने उसे खाने का प्रस्ताव दिया और बदले में रात गुजारने के लिए जगह मांगी.तांगे वाले ने पूछा, क्या तुम पाकिस्तान के लिए खेलते हो?शोएब ने जवाब दिया, अभी नहीं. लेकिन एक दिन जरूर खेलूंगा.

उन्होंने उससे वादा किया कि अगर वह पाकिस्तान टीम में चुन लिए गए तो वापस आकर उससे मिलेंगे.

कुछ साल बाद भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करके जब शोएब स्टार बनकर लौटे, तो वह अपना वादा निभाने लाहौर पहुंचे. उन्होंने अजीज खान को ढूंढ़ निकाला. दोनों ने साथ खाना खाया. फिर तांगे वाले ने उन्हें उसी रास्ते पर तांगे की सवारी कराई जहां वह उन्हें ट्रायल के लिए छोड़ने गया था.

पीआईए टीम में चयन के बाद शोएब कराची पहुंच गए. लेकिन रहने का इंतजाम नहीं किया गया. उन्हें लियाकताबाद और लालूखेत जैसे इलाकों में साधारण कमरों में रहना पड़ा.

यह वह दौर था जब कराची में राजनीतिक हिंसा और ऑपरेशन चल रहे थे. शहर में अक्सर हड़तालें होती थीं. फायरिंग होती थी. कर्फ्यू लग जाता था.शोएब बताते हैं कि उन्हें रोजाना कई किलोमीटर पैदल चलकर नेशनल स्टेडियम जाना पड़ता था. कई बार अचानक गोलीबारी शुरू हो जाती थी. तब वह जमीन पर बैठ जाते थे ताकि किसी गोली का निशाना न बन जाएं.मई 2002 में कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड टीम के होटल के बाहर बड़ा बम धमाका हुआ था.शोएब बताते हैं कि वह अपने कमरे में बैठे थे. अचानक तेज धमाका हुआ और बाहर आग दिखाई दी. उन्हें लगा जैसे कान के पर्दे फट गए हों.राशिद लतीफ ने कमरे का दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला.नीचे पहुंचने पर उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को रोते हुए देखा.

वह बेहद डरे हुए थे. शोएब कहते हैं कि इस घटना का उन पर गहरा मानसिक असर पड़ा और लंबे समय तक वह कराची आने से डरते रहे.साल 2008 में आईपीएल का पहला सीजन शुरू हुआ. शोएब अख़्तर भी इसका हिस्सा बने.वह बताते हैं कि उस समय आईपीएल और आईसीएल दोनों लीग शुरू हो रही थीं. अभिनेता शाहरुख खान ने उनसे संपर्क किया और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलने का प्रस्ताव दिया.

भारत में जेन जी के प्रदर्शन को चीन के टिप्पणीकार क्यों बता रहे पीएम मोदी की नाकामी

चीनी टिप्पणीकारों ने बीते दिनों भारत में युवाओं के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के सबसे बड़े राजनीतिक झटकों में से एक बताया.उन्होंने इन प्रदर्शनों को भारत की शिक्षा व्यवस्था में युवाओं का घटता भरोसा बताया है.इस मामले में चीन के प्रमुख सरकारी मीडिया ने खुद को काफी हद तक तथ्यात्मक रिपोर्टिंग तक सीमित रखा. लेकिन फुदान यूनिवर्सिटी के एक स्कॉलर ने तर्क दिया कि पीएम मोदी की आर्थिक नीतियां भारत के शिक्षित युवाओं के लिए अवसर पैदा करने में नाकाम रही हैं.चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'वीबो' पर यूजर्स ने भी इन विरोध प्रदर्शनों को भारत की शिक्षा व्यवस्था और शासन की कमजोरियों को उजागर करने वाला बताया.चीन के कुछ लोगों ने इसे एक भारतीय आलोचक के वीडियो पोस्ट करने के अवसर के रूप में भी इस्तेमाल किया.नीट यूजी की प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में युवा दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 जून से प्रदर्शन कर रहे थे.इसके अलावा देशभर में भी कई जगह युवाओं ने प्रदर्शन किया था.

चीनी टिप्पणीकारों ने भारत में हाल ही में देशभर में युवाओं के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के पीछे युवाओं में बेरोजगारी को लेकर व्यापक चिंताओं को वजह बताया.इन प्रदर्शनों की वजह से धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा.चीनी कमेंटेटर्स ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का ₹सबसे बड़ा राजनीतिक झटका₹ कहा भारत में विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने किया. इसकी शुरूआत नीट-यूजी की प्रवेश परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने के बाद शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और अन्य शिक्षा सुधारों की मांग को लेकर हुई थी.कॉकरोच जनता पार्टी एक ऑनलाइन व्यंग्य के तौर पर बनी थी.इस आंदोलन पर विस्तृत टिप्पणी में, दक्षिण एशियाई अध्ययन में विशेषज्ञता रखने वाले फुदान यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता चेन झुओ ने 27 जुलाई को राष्ट्रवादी खबरों और कमेंट्स से जुड़ी वेबसाइट गुआनचा.सीएन पर की.उन्होंने कहा कि यह सत्ता में 12 वर्षों के दौरान भारत के प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) के लिए सबसे गंभीर राजनीतिक झटकों में से एक बन गया है, जो उन्हें झेलना पड़ा है.उनके मुताबिक, एक मजबूत राजनीतिक नेता का अधिकार अडिग रुख पर आधारित होता है. मोदी को झुकने के लिए मजबूर होना इस बात का संकेत है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है, जिससे यह विरोध प्रदर्शन उनके कार्यकाल के सबसे बड़े राजनीतिक झटकों में से एक बन गया है.

टिप्पणी में कहा गया कि यह संकट सबसे पहले दिखाता है कि मोदी की आर्थिक विकास की नीतियां बड़ी संख्या में शिक्षित भारतीय युवाओं को अवसर देने में सक्षम नहीं हैं.

क्या ईरान के इस 'खतरनाक' प्लान ने ट्रंप को हमला करने से रोक दिया है?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ईरान पर अपने संभावित हमले को रोकने का एलान किया है.वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया है इससे पहले उन्होंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की थी.दरअसल अमेरिका और सऊदी अरब ने संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों को निशाना बनाते हुए सार्वजनिक तौर पर घोषित पहला हमला किया था.

माना जा रहा था कि इसके बाद ट्रंप ईरान के खिलाफ फिर बड़ा हमला कर सकते हैं. हालांकि ये आशंका फिलहाल टल गई है.कुछ मीडिया खबरों के मुताबिक ईरान ने हमले की स्थिति के लिए एक ऐसा प्लान बनाकर रखा है, जो पूरी दुनिया को फिर से गंभीर तेल संकट में डाल सकता है.इन खबरों के मुताबिक हमले की स्थिति में ईरान खाड़ी देशों के तेल कुओं पर बड़े हमले करेगा.ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने शनिवार को तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के वरिष्ठ अधिकारियों से अलग-अलग फोन पर बातचीत में यह बात कही थी कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उनका देश निर्णायक हमले करेगा.

यह बातचीत ऐसे समय हुई जब कुछ घंटे पहले कुवैत की सेना ने दावा किया था कि उसने ईरान की ओर से कुछ अहम ठिकानों पर भेजे गए दुश्मन के ड्रोन मार गिराए हैं.अरागची ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान से कहा कि अगर ईरान के खिलाफ कोई ₹आक्रामक कार्रवाई₹ हुई तो उसका निर्णायक जवाब दिया जाएगा.बाद में अरागची ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से भी कहा कि अगर अमेरिका और इसराइल हमला करते हैं, या क्षेत्र का कोई देश ऐसी कार्रवाई में शामिल होता है, तो ईरान उसी हिसाब से जवाब देगा.एक्सियोस के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शनिवार को राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात की.ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से जुड़े मीडिया संस्थान नूर न्यूज ने शनिवार को कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा ढांचे पर हमला किया, तो ईरान सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के तेल क्षेत्रों, साथ ही कतर और इसराइल के तेल और गैस फील्ड को निशाना बनाएगा.आईआरजीसी से जुड़ी समाचार एजेंसी तस्नीम का कहना कि ईरान ने एक सूची बना रखी है.इसमें इस बात का जिक्र है कि खाड़ी के किन-किन देशों के किन तेल और गैस ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा.हालांकि ये पूरी सूची के बारे में सटीक जानकारी नहीं है. लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर के अहम तेल और गैस ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है.लिस्ट में दुनिया का सबसे बड़ा पारंपरिक तेल क्षेत्र घवार, अबकैक तेल प्रसंस्करण संयंत्र और खुरैस ऑयल फील्ड शामिल हैं. ये तीनों सऊदी अरब के तेल उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं.

संयुक्त अरब अमीरात में ईरान ने कथित तौर पर जाकुम और ऑयल फील्ड और रुवैस रिफाइनरी को संभावित को निशाना बना सकता है.

ईरान के लिए इसराइली लोगों को निशाना बनाने वाला 'फॉक्सट्रॉट नेटवर्क' क्या है

मैं एक खतरनाक मिशन पर जा रहा हूँ.' यह वह छोटा सा संदेश था जो 19 साल के नॉर्वे के रहने वाले जोहान्स नैटलैंड ने ब्रिटेन जाने से पहले अपनी प्रेमिका को भेजा था. 19 मार्च 2025 को, नैटलैंड को उत्तरी इंग्लैंड के हडर्सफील्ड शहर के एक होटल में दो बंदूकों, 19 राउंड गोला-बारूद और 2,000 पाउंड (2,680 डॉलर) के नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया था.इस सप्ताह, एक ब्रिटिश अदालत ने उन्हें ईरान से जुड़े एक स्वीडिश आपराधिक गिरोह के आदेश पर हत्या की साज़िश रचने का दोषी पाया.स्वीडिश संगठित अपराध गिरोह को फॉक्सट्रॉट नेटवर्क के नाम से जाना जाता है और ब्रिटिश अभियोजकों का कहना है कि इसने नैटलैंड को 'कॉन्ट्रैक्ट किलिंग' को अंजाम देने के लिए ब्रिटेन भेजा था.

फॉक्सट्रॉट एक बेहद हिंसक समूह है जो किशोरों को भाड़े के हत्यारों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए पहले से ही कुख्यात है.इस तरह के मामलों को यूरोपीय संघ की कानूनी प्रवर्तन एजेंसी यूरोपोल ने 'हिंसा का काम' करना करार दिया है. अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि नैटलैंड को ब्रिटेन में किसे मारने के लिए भेजा गया था.लेकिन फुटबॉल से प्यार करने वाला एक युवक ऐसे आपराधिक गिरोह के साथ कैसे जुड़ गया जिसने उसे हत्या करने के लिए काम पर रखा था?फॉक्सट्रॉट और उसके नेता रावा माजिद अलग-अलग यूरोपीय देशों में किशोरों और युवाओं का अपने मकसद के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं और फॉक्सट्रॉट का ईरानी सरकार से क्या संबंध है?13 मार्च 2025 को ब्रिटेन में नैटलैंड की गिरफ़्तारी से ठीक एक सप्ताह पहले, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने घोषणा की कि उसने ईरानी सरकार के खिलाफ ट्रंप प्रशासन के 'अधिकतम दबाव' नीति के रूप में फॉक्सट्रॉट और माजिद पर प्रतिबंध लगा दिए हैं.अपने बयान में, अमेरिका ने आरोप लगाया कि फॉक्सट्रॉट और माजिद 'ईरान के खुफिया मंत्रालय के साथ मिलकर काम करते हैं.'एक महीने बाद ब्रिटेन ने यूरोप के कई हिस्सों में टार्गेट्स को निशाना बनाने में उनकी भूमिका और ईरानी सरकार के नेटवर्क और उसके नेता पर प्रतिबंध लगा दिया.

पिछले साल, स्वीडिश समाचार पत्रों 'डैगेन्स न्येहटर' और 'एक्सप्रेसन' ने इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों और सूचनाओं का हवाला देते हुए, विस्तृत रिपोर्टों में आरोप लगाया कि माजिद 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के लिए काम करते हैं.'यह समूह पहली बार 2023 में सुर्खियों में आया था. उसी साल जून में एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसकी आवाज 20 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे स्वीडन का उप्साला शहर हिल गया. विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास के पांच घर क्षतिग्रस्त हो गए. पुलिस का कहना है कि विस्फोट में एक युवती की मौत हो गई, जो शायद बम विस्फोट का टार्गेट नहीं थी.उसी साल स्टॉकहोम के बाहरी इलाकों में कई सशस्त्र और खूनी झड़पों की खबरें सामने आईं.इन झड़पों में कई लोगों की मौत हुई, जिनमें ज्यादातर किशोर थे और इससे देश में व्यापक भय का माहौल फैल गया.जनवरी 2024 के अंतिम दिन, स्टॉकहोम में इसराइली दूतावास के एक कर्मचारी ने दूतावास परिसर के अंदर एक विस्फोटक उपकरण पाया.स्वीडिश राष्ट्रीय पुलिस की बम निरोधक इकाई ने दूतावास परिसर से इसे हटाया और इसे नियंत्रित विस्फोट द्वारा नाकाम कर दिया.इसराइली राजदूत ने इस घटना को 'आतंकवादी हमले का प्रयास' बताया. इन घटनाओं के संबंध में स्वीडन के दो हिंसक आपराधिक समूहों, 'फॉक्सट्रॉट' और 'रूंबा' का नाम लिया गया और स्वीडन, अमेरिका और इसराइल की सरकारों ने ईरान पर 'उनके साथ सहयोग करने' का आरोप लगाया.30 मई 2024 को, स्वीडिश सुरक्षा सेवा (सैपो) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरानी सरकार पर 'अपराधियों के एक नेटवर्क के माध्यम से स्वीडन और अन्य देशों में गैरकानूनी और हिंसक कृत्यों को अंजाम देने' का आरोप लगाया.स्वीडिश सुरक्षा सेवा के प्रमुख डैनियल स्टेलिंग ने कहा, ₹हालांकि इन आपराधिक गिरोहों के टार्गेट समूह मुख्य रूप से ईरानी सरकार के विरोधी हैं, लेकिन इसराइल जैसे देशों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ वे यहूदी संगठनों और संस्थानों को भी वे निशाना बनाते हैं नीदरलैंड्स ने भी ईरान पर इसी तरह के आरोप लगाए हैं. साल 2015 और 2017 में डच धरती पर ईरानी शासन के विरोधी दो समूहों के नेताओं की हत्या के बाद, डच खुफिया और सुरक्षा सेवा, एआईवीडी ने ईरान पर इन हत्याओं को अंजाम देने के लिए 'डच आपराधिक समूहों को सुपारी देने' का आरोप लगाया था.पिछले साल, ब्रिटेन के विदेश कार्यालय ने यह भी घोषणा की थी कि ईरान 'राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हिंसक कृत्यों को अंजाम देने के प्रयास में हिंसक आपराधिक समूहों के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है.'स्वीडिश सुरक्षा सेवा, जिसने पहले चीन और रूस को देश के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा बताया था, उसने अब इस सूची में ईरान को भी शामिल कर लिया है.स्वीडिश सुरक्षा सेवा के अनुसार, ईरान ने पहले भी अन्य यूरोपीय देशों में अपने विरोधियों को चुप कराने और अपने शासन के लिए कथित खतरों का मुकाबला करने के मकसद से हिंसा का इस्तेमाल किया है.

सैपो ने दावा किया है कि हाल के सालों में, उसने स्वीडन में 'ईरानी सुरक्षा सेवाओं और आपराधिक नेटवर्क से जुड़ी हत्या की कई साज़िशों को अंजाम देने से रोका है.'ईरान ने इन आरोपों का पुरजोर खंडन किया है और स्वीडन पर 'इसराइल की झूठी जानकारी' को मान लेने का आरोप लगाया है.फॉक्सट्रॉट नेटवर्क का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति रावा माजिद हैं, जिन्हें 'कुर्दिश फॉक्स' के नाम से जाना जाता है.स्वीडिश मीडिया का कहना है कि उनका परिवार इराकी कुर्दिस्तान से है और उनका जन्म ईरान में हुआ था. कुछ समय बाद उनका परिवार स्वीडन आ गया और वो उप्साला में पले-बढ़े.इंटरपोल को माजिद की तलाश है. उन पर 'नशीली दवाओं की तस्करी, हत्या और हत्या में संलिप्तता, हिंसा, हथियारों का इस्तेमाल' और अन्य अपराधों सहित कई आरोप हैं.

विशेषज्ञों का दावा- 'दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान सीजेपी समर्थकों की चोटें पैलेट गन से लगने जैसी'

बीबीसी से बात करने वाले स्वतंत्र बैलिस्टिक विशेषज्ञों ने कहा है कि पिछले सप्ताह दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के कुछ समर्थकों को लगी चोटें पैलेट गन की थीं.20 जुलाई को सेंट्रल दिल्ली में व्यापक हिंसा देखने को मिली, जब हजारों प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा सुधारों और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की.इस दौरान पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों को भीड़ के ऊपर बेरहमी से लाठियों, डंडों और आंसू गैस से हमला करते देखा गया.

दिल्ली पुलिस ने बताया कि उसके 60 प्रदर्शनकारी और उनके 118 जवान घायल हुए हैं. जबकि सीजेपी ने कहा कि घायल प्रदर्शनकारियों की संख्या आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा थी.

इस कार्रवाई के कई दिन गुजर जाने के बाद भी सरकार ने उन मीडिया रिपोर्टों की पुष्टि नहीं की, जिनमें कहा गया कि प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था.लेकिन बीबीसी कम से कम चार ऐसे मामलों की पुष्टि करने में कामयाब रहा है, जहां प्रदर्शनकारियों का अस्पतालों में उन घावों के लिए इलाज किया गया है, जिनके बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि वे पैलेट गन के कारण हुए हैं.पैलेट गन ऐसी शॉटगन होती हैं जिन्हें मूल रूप से पक्षियों के शिकार के लिए बनाया गया था. इनमें 'बर्डशॉट' नामक कारतूस का इस्तेमाल होता है, जिनमें 200 से 400 तक छोटे धातु के छर्रे भरे होते हैं.

जब इन्हें भीड़ के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, तो ये छर्रे एक विस्तृत दायरे में फैल जाते हैं और लोगों में कोई अंतर किए बिना उन्हें कहीं भी इससे चोट लग सकती है. इसी वजह से कई देशों में इन बंदूकों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है.बीबीसी ने दो घायल शख़्स से बात की है, जिनका मानना है कि वे सुरक्षा बलों की ओर से चलाई गई पैलेट गनों के छर्रों से घायल हुए थे. हमने इन दोनों और एक तीसरे घायल की तस्वीरें और वीडियो दो स्वतंत्र हथियार एवं फोरेंसिक विशेषज्ञों को भी दिखाईं.इसके अलावा, एक अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि एक चौथे व्यक्ति का भी इलाज पैलेट गन के छर्रों से लगी चोटों के लिए किया गया था.विशेषज्ञों का कहना है कि शरीर पर बने दर्जनों छोटे-छोटे गोल छेद बर्डशॉट से लगी चोटों के स्पष्ट संकेत हैं.ब्रिटेन स्थित बैलिस्टिक्स फोरेंसिक वैज्ञानिक फिलिप बॉयस ने बीबीसी को बताया, ₹दिखाई गई चोटें निश्चित रूप से पैलेट गन से लगी हैं, और इस्तेमाल किया गया हथियार 12-गेज पंप-एक्शन शॉटगन है.उन्होंने कहा, ₹ये छर्रे के घाव वास्तव में काफी घातक हो सकते हैं, खासकर करीब से लगने पर.उन्होंने यह भी कहा, जो घाव मैंने देखे (दिल्ली में) वे निकट दूरी से नहीं लगी हैं, बल्कि कम से कम 50 फुट की दूरी से लगी हैं. लेकिन फिर भी वे 100 फुट की दूरी से भी घातक और संभावित रूप से जानलेवा हो सकती हैं.

ब्रिटेन स्थित आमार्मेंट रिसर्च सर्विसेज के निदेशक एनआर जेनजेन-जोन्स ने बीबीसी से कहा कि ₹प्रदर्शनों की तस्वीरों और वीडियो में पुलिस को भीड़ नियंत्रण के लिए शॉटगन का इस्तेमाल करते हुए देखा जा सकता है.उन्होंने यह भी कहा कि घायलों की तस्वीरों में दिखाई देने वाली ₹चोटें बर्डशॉट (छर्रों) के इस्तेमाल से होने वाली चोटों से काफी हद तक मेल खाती हैं. एनआर जेनजेन-जोन्स ने कहा, दुनिया के कई देशों में कम घातक हथियारों के तौर पर शॉटगन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भारत की कानून लागू करने वाली एजेंसियों का भीड़ नियंत्रण के दौरान छोटे सीसे (लेड) के छर्रों वाले शॉटगन कारतूस इस्तेमाल करने का लंबा इतिहास रहा है.वे आगे कहते हैं कि इन्हें 'बर्डशॉट' कहा जाता है और बर्डशॉट वाले कारतूस लगाए जाने पर शॉटगन को कई बार 'पैलेट गन' भी कहा जाता है.उन्होंने कहा, लेकिन ये छर्रे सुरक्षित नहीं होते. इनसे ऐसी चोटें लग सकती हैं जो किसी की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दें. कुछ मामलों में ये जानलेवा भी साबित हो सकती हैं. इसके अलावा ये शरीर में जहरीला सीसा छोड़ जाते हैं. कई बार इसे सुरक्षित तरीके से निकालना भी मुश्किल होता है.इसी वजह से कई देशों ने पैलेट गनों पर रोक लगा दी है या इनके इस्तेमाल पर कड़ी पाबंदी लगा रखी है.फिलिप बॉयस का कहना है कि ब्रिटेन में पैलेट गनों का इस्तेमाल आमतौर पर पक्षियों के शिकार के लिए किया जाता है. ये आसानी से उपलब्ध भी हैं. लेकिन उनके मुताबिक, उन्हें ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है जिसमें भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया हो.ह्यूमन राइट्स वॉच के संकलित किए आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि इनसे कई हजार लोग घायल हुए हैं और कम से कम 17 लोगों की मौत हुई है. पैलेट गन से चोट की वजह से दर्जनों लोग अंधे हो गए.

अगर इसकी पुष्टि हो जाती है कि सुरक्षा बलों ने दिल्ली में पैलेट गन का इस्तेमाल किया था तो यह पहला मौका होगा जब भारत ने अपनी राजधानी में नागरिकों पर इनका इस्तेमाल किया हो.हमने जिन दो युवकों से बात की, उन्होंने हमें बताया कि वे 20 जुलाई को शाम चार बजे के बाद संसद के पास स्थित एक प्रमुख केंद्र कनॉट प्लेस में घायल हो गए थे.मोहित (नाम बदला हुआ) ने बताया कि जब उन्होंने एक सुरक्षाकर्मी को अपनी ओर बंदूक ताने देखा, तो वह मुड़कर उल्टी दिशा में भागने लगे.

28 वर्षीय पत्रकार ने बीबीसी को बताया, ₹दो-तीन सेकंड बाद मुझे अपनी दाहिनी बांह और पीठ पर जलन महसूस हुई.मोहित के मुताबिक, वह दर्द के बावजूद भागते रहे. बाद में वह एक कैफे पहुंचे. वहां उन्होंने पानी की एक बोतल खरीदी और अपने घाव धोए.उन्होंने कहा, ₹तभी मैंने अपने हाथ और पीठ के ऊपरी हिस्से पर छोटे-छोटे गोल छेद देखे. मैं पूरी तरह घबरा गया था.₹

छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता में सुधार : सुशासन, डिजिटलीकरण और जन-राहत का नया सवेरा

रायपुर। राजस्व प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से भूमि रिकॉर्ड, नामांतरण और रजिस्ट्री जैसे कार्य ऑनलाइन और पारदर्शी बनाए गए हैं। इसके मुख्य लाभों में ऑटो म्यूटेशन, मोबाइल ऐप से रिकॉर्ड डाउनलोड और डिजिटल भुगतान शामिल हैं। आम जनता के लिए राजस्व विभाग से जुड़े काम हमेशा से पेचीदा और समय लेने वाले माने जाते रहे हैं। जमीन के नामांतरण से लेकर कोर्ट के चक्कर काटने और नामांतरण-सीमांकन में होने वाली देरी से आम नागरिक अक्सर परेशान रहता था। इसी प्रशासनिक जटिलता को समाप्त कर प्रक्रिया को पारदर्शी, सुलभ और जन-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 में कई युगांतरकारी और जनोन्मुख संशोधन किए हैं। यह सुधार न केवल आधुनिक दौर की डिजिटल जरूरतों को पूरा करते हैं, बल्कि राज्य में सुशासन की नींव को और अधिक मजबूत करते हैं। इन संशोधनों की सबसे बड़ी खासियत राजस्व प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण है। अब धारा 33 के तहत नोटिस और आधिकारिक सूचना प्रेषित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कानूनी मान्यता दे दी गई है। इसके साथ ही, धारा 30 में संशोधन करते हुए राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए अभिलेखों, प्रकरणों और फाइलों के डिजिटल प्रेषण को अनिवार्य किया गया है। इतना ही नहीं, भूमि सीमांकन और नक्शों से जुड़ी विवादित स्थितियों से निपटने के लिए धारा 107 के तहत अधिसूचित जिओ-रेफ्रेंस्ड नक्शों को अधिमान्यता दी गई है, जिससे जमीन से जुड़े सटीक आंकड़े और सीमांकन पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हो सकेंगे। जमीनों के अनावश्यक विखंडन और भू-अर्जन के दौरान होने वाले फजीवाड़े पर लगाम कसने के लिए भी कड़े कदम उठाए गए हैं। धारा 70 में किए गए संशोधन के अनुसार अब 05 डिसमिल से कम कृषि भूमि के बंटवारे पर रोक लगा दी गई है, ताकि कृषि जोत का आकार व्यावहारिक बना रहे। वहीं धारा 165, 172 और 178 में बदलाव कर यह सुनिश्चित किया गया है कि भू-अर्जन की प्रक्रिया के लिए अधिसूचना या आशय पत्र जारी होते ही संबंधित भूमि के अंतरण, व्यपवर्तन और खाता विभाजन पर तुरंत रोक लग जाए, जिससे किसी भी तरह के अवैध लाभ या धोखाधड़ी की गुंजाइश न रहे।

आम जनता को सबसे बड़ी राहत जमीन के नामांतरण और पारिवारिक उत्तराधिकार के नियमों में मिली है। धारा 110 में किए गए क्रांतिकारी संशोधनों के तहत अब 'स्वतः नामांतरण' की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत पंजीयन (रजिस्ट्री) विभाग को ही नामांतरण का वैधानिक अधिकार दे दिया गया है।

मलेरिया के 3 नए मरीज मिले बिलासपुर कोटा में

बिलासपुर। कोटा क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां रविवार को तीन नए मरीज सामने आए हैं। नए मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। औरापारा और केंदा सहित प्रभावित ग्रामीण इलाकों में पिछले 14 दिनों से लगातार स्वास्थ्य शिविर लगाकर बीमार लोगों की जांच और इलाज किया जा रहा है। कोटा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग की जांच में अब तक कुल 33 मरीजों में मलेरिया की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से 16 एक्टिव मरीजों का फिलहाल इलाज चल रहा है। रविवार को तीन नए मरीज मिलने के बाद जिला मलेरिया अधिकारी डा. वीके वैष्णव एवं कृष्णा कुमारी के नेतृत्व में विशेष टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का मोर्चा संभाल लिया है। स्वास्थ्य शिविरों में आने वाले ग्रामीणों की तत्काल रक्त जांच की जा रही है। इसके साथ ही मितानिनों के माध्यम से गांव-गांव में जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीणों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने घरों और आसपास के गड्ढों में ठहरे पानी को तुरंत खाली करें, परिसर में साफ-सफाई रखें और शाम के समय मच्छर भगाने के लिए धुआं करें। विभाग का पूरा ध्यान मच्छरों के लार्वा को नष्ट करने और नए मरीजों की पहचान कर समय पर इलाज मुहैया कराने पर है। बारिश के मौसम में ग्रामीण इलाकों में जगह-जगह जलजमाव होने से मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर जलभराव वाले स्थानों की जांच कर रही हैं। शिविर में बुखार की शिकायत लेकर पहुंचने वाले हर व्यक्ति का कार्ड टेस्ट कराया जा रहा है, ताकि शुरुआती दौर में ही बीमारी को पकड़ा जा सके।

पार्षद परिवार के खिलाफ FIR दर्ज, 5 करोड़ की जमीन डील में फजीर्वाड़ा का आरोप

दुर्ग। जिले में करोड़ों रुपए की जमीन के सौदे को लेकर कांग्रेस नेत्री और भिलाई नगर निगम की एमआईसी सदस्य रीता सिंह, उनके पति रमेश चंद्र सिंह और बेटे मानवचंद सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई पाटन स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत के आदेश के बाद उतई पुलिस ने की है। मामला रायपुर निवासी बीपी सिंह की शिकायत से जुड़ा है। बीपी सिंह ने कोर्ट में निजी परिवाद दायर किया था। शिकायत पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ माना और तीनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही उतई पुलिस को 15 दिन के भीतर एफआईआर और कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश भी दिया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक साल 2024 में छांटा स्थित गिट्टी खदान और उससे लगी 25 एकड़ जमीन का सौदा 4 करोड़ 50 लाख रुपए में तय हुआ था। इस सौदे में एक चैन मशीन और दो हाइवा वाहन भी शामिल थे। शिकायत में बताया गया है कि कुल 25 एकड़ जमीन में से 13 एकड़ जमीन आरोपियों के नाम थी। इसके अलावा 7 एकड़ दान की जमीन और 5 एकड़ सरकारी लीज की जमीन भी इस सौदे का हिस्सा बताई गई थी। प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने सौदे के लिए कुल 4 करोड़ 39 लाख रुपए चेक के जरिए दिए। इसमें 2 करोड़ 90 लाख रुपए मानवचंद सिंह के खाते में, 1 करोड़ रुपए रीता सिंह के खाते में और बाकी रकम रमेश चंद्र सिंह के खाते में जमा कराई गई। पैसे भेजने के बाद भी आरोपियों ने सिर्फ 7 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराई। बाकी जमीन का न तो नामांतरण कराया गया और न ही सौदे की दूसरी शर्तें पूरी की गईं। शिकायतकर्ता का कहना है कि बाद में जब उन्होंने दस्तावेजों की जांच कराई तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। उनके मुताबिक, जिन लोगों ने जमीन बेचने का दावा किया था, वे असली जमीन मालिक ही नहीं थे। आरोप है कि तीनों ने मिलकर फर्जी इकरारनामा और दूसरे दस्तावेज तैयार किए। इसमें असली जमीन मालिकों की जगह दूसरे लोगों के हस्ताक्षर कराए गए और गलत जानकारी के आधार पर करोड़ों रुपए का सौदा किया गया। इन्हीं आरोपों के आधार पर शिकायतकर्ता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी और साजिश का मामला बनता है। इसके बाद उतई पुलिस को संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया।

कौही के प्राचीन शिव मंदिर का रहस्य

पाटन। रानीतराई से तीन किलोमीटर दूर खारून नदी के तट पर स्थित ग्राम कौही का प्राचीन शिव मंदिर धार्मिक और सामाजिक एकता का पर्याय बन चुका है। यहां विराजमान स्वयंभू शिवलिंग की सबसे बड़ी विशेषता इसका लगातार बढ़ता आकार है। वर्तमान में शिवलिंग की ऊंचाई लगभग छह फीट व परीधि पांच मीटर है। खुदाई के बाद से लेकर अब तक स्वयंभू शिवलिंग का दूसरा छोर नहीं मिला है। मंदिर स्थापना और शिवलिंग को लेकर जनश्रुति है कि क्षेत्र के पुराना गांव प्रमुख पटेल मालगुजार को खुदाई करते समय यह शिवलिंग मिला था। महाकाली एवं हनुमान मंदिर परिसर धर्म नगरी कौही समिति के अध्यक्ष योगेश्वर साहू, सचिव राजेश साहू, कोषाध्यक्ष हेमलाल साहू, उपाध्यक्ष सुनीता यदु, मुकेश साहू, नारायण साहू ने बताया कि खारून नदी के किनारे 11 एकड़ भू-भाग में फैले मुख्य मंदिर में विराजमान स्वयंभू शिवलिंग खुदाई करते हुए खंडित हो गया था। तब पुराने मलागुजार गांव प्रमुख पटेल को स्वप्न में महादेव से साक्षात्कार हुआ।

नाबालिग को धमकाकर लाखों रुपये और जेवर वसूले, अरकके बेटे समेत चार गिरफ्तार

बिलासपुर। जिले के सरकंडा थाना क्षेत्र में नाबालिग को डराकर लाखों रुपये और सोने-चांदी के जेवरात वसूलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी आयुष यादव समेत चार युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर नाबालिग को धमकाकर करीब 14 लाख 50 हजार रुपये नकद और लगभग 450 ग्राम सोने के जेवरात लेने का आरोप है। जानकारी के अनुसार, सरकंडा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक बुजुर्ग ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी पोती को कुछ युवकों ने डराया-धमकाया और उससे बड़ी रकम वसूली। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने नाबालिग को मानसिक रूप से परेशान कर एटीएम, फोन-पे और अन्य माध्यमों से करीब 14.50 लाख रुपये हासिल किए। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने घर में रखे करीब 450 ग्राम सोने के जेवरात भी नाबालिग को डराकर ले लिए। इतना ही नहीं, आरोपियों पर परिवार की छोटी पोती को चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकंडा थाना पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक अचानक बड़ी मात्रा में पैसे खर्च कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ और जांच के दौरान मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी आयुष यादव और उसके तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में आयुष यादव पिता धर्मेंद्र यादव उम्र 22 वर्ष, निवासी मोपका विवेकानंद नगर, थाना सरकंडा, बिलासपुर शामिल है। इसके अलावा आदर्श शर्मा पिता रमाकांत शर्मा उम्र 19 वर्ष, निवासी दीनदयाल कॉलोनी बहतराई, थाना सरकंडा, प्रिंस साहू पिता नंदकिशोर साहू उम्र 18 वर्ष 3 माह, निवासी दीनदयाल कॉलोनी बहतराई और आदित्य पांडे पिता हेम कुमार पांडे उम्र 19 वर्ष, निवासी बजरंग चौक के पीछे आरके नगर, थाना सरकंडा को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी आयुष यादव के पिता धर्मेंद्र यादव पुलिस विभाग में एएसआई के पद पर पदस्थ हैं। वहीं पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ पहले से भी अन्य शिकायतें सामने आई हैं। आरोप है कि आयुष यादव अपने साथियों के साथ मिलकर गैंग बनाकर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने बताया कि मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है

दुर्ग पुलिस में सेवानिवृत्त अधिकारियों को सम्मानपूर्वक विदाई, रर‍ढ ने दी बधाई

दुर्ग। पुलिस विभाग में वर्षों तक अपनी सेवाएं देने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों के सम्मान में दुर्ग पुलिस द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला दुर्ग में आयोजित कार्यक्रम में सेवानिवृत्त हो रहे तीन अधिकारियों को सम्मानपूर्वक विदाई दी गई। इस दौरान अधिकारियों के योगदान और सेवाकाल को याद करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। 1 अगस्त 2026 को आयोजित इस सम्मान समारोह में पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हो रहे उप निरीक्षक सौमित्र भोई, अ'२ङ्क फ्तीं - दुर्ग शहर में आकृषित पार्थिव शिवलिंग का मधुर गीतों एवं मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक हुआ सहायक उप निरीक्षक रोहित मरकाम एवं सहायक उप निरीक्षक तालसिंह को सम्मानित किया गया। तीनों अधिकारियों ने पुलिस विभाग में लगभग 35 से 40 वर्षों तक अपनी सेवाएं दीं और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया। कार्यक्रम की शुरूआत उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग विजय अग्रवाल द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के स्वागत के साथ हुई। उन्होंने सभी अधिकारियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया और उनके लंबे सेवाकाल के लिए आभार व्यक्त किया। समारोह के दौरान सेवानिवृत्त अधिकारियों ने पुलिस सेवा के दौरान अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने अपने कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं, चुनौतियों और जिम्मेदारियों का उल्लेख करते हुए वर्तमान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि पुलिस सेवा अनुशासन, समर्पण और जनसेवा का महत्वपूर्ण माध्यम है। सेवानिवृत्त अधिकारियों ने अपने अनुभवों के माध्यम से बताया कि पुलिस विभाग में काम करते हुए जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का संदेश दिया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने कहा कि सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा पुलिस विभाग को दी गई सेवाएं हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। सेवानिवृत्त अधिकारियों का अनुभव विभाग की अमूल्य संपत्ति है और उनका मार्गदर्शन हमेशा पुलिस परिवार के लिए प्रेरणादायक रहेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग अपने सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों के स्वस्थ, सुखद और सम्मानपूर्ण जीवन की कामना की।

फिल्म देखने पहुंचे युवाओं में विवाद, झंकार टॉकीज में मारपीट

जगदलपुर। हॉलीवुड फिल्म को लेकर युवाओं में दिख रहा उत्साह जगदलपुर में अचानक हिंसक विवाद में बदल गया। शहर के झंकार टॉकीज में फिल्म देखने पहुंचे युवाओं के दो गुटों के बीच मामूली कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच लात-घूंसे चलने लगे और सिनेमाघर के अंदर रखी टेबल-कुर्सियां भी एक-दूसरे पर फेंकी गईं। जानकारी के अनुसार, घटना जगदलपुर शहर स्थित झंकार टॉकीज की है। बताया जा रहा है कि इसी दौरान किसी बात को लेकर युवाओं के दो समूहों के बीच विवाद शुरू हो गया। शुरूआत में मामला बहस तक सीमित था, लेकिन कुछ ही देर में विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों पक्षों के युवक एक-दूसरे से भिड़ गए और सिनेमाघर परिसर में मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान वहां मौजूद दर्शकों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। लोग अपनी सुरक्षा के लिए इधर-उधर भागने लगे। आरोप है कि मारपीट के दौरान एक युवक पर हथौड़े से हमला किया गया। हमले में युवक के सिर पर गंभीर चोट आई, जिसके बाद उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने घायल युवक के सिर में छह टांके लगाए हैं। फिलहाल घायल का इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई। मारपीट के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने झंकार टॉकीज में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद होने की बात सामने आई है। पुलिस फुटेज के आधार पर मारपीट में शामिल युवकों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। आरोपियों की पहचान होने के बाद उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

दूधिया बदन, 70 साल का बच्चा..' अन्नू कपूर ने तमन्ना भाटिया के लिए कही ओछी बात, अपनी उम्र का तो लिहाज कर लेते!

अन्नू कपूर ने हाल ही में तमन्ना भाटिया पर कमेंट किया और उनकी 'मिल्की ब्यूटी' को लेकर काफी कुछ बोल गए। अन्नू कपूर ने कहा कि 'आहा, माशाअल्लाह क्या दूधिया बदन है। बच्चे कितने साल के हो जाते हैं? 70 साल का बच्चा भी सो सकता है!' इसके बाद भी वो रुके नहीं और काफी कुछ बोले।

तमन्ना भाटिया पर क्या बोल गए अन्नू कपूर

अन्नू कपूर जब भी किसी इंटरव्यू में आते हैं तो वो कोई ऐसी बात जरूर कहते हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। ये दिग्गज एक्टर अपनी दमदार आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं लेकिन हाल ही में इन्होंने तमन्ना भाटिया के लिए इतनी ओछी बातें कही हैं कि आप भी सोचेंगे कि उम्र के इस पड़ाव पर थोड़ा तो लिहाज कर लेते! उनकी बात किसी फिल्म से नहीं, बल्कि तमन्ना भाटिया के धमाकेदार गाने 'आज की रात' पर किए गए कमेंट पर है। उनके मजेदार और चुटीले अंदाज ने इंटरनेट पर लोगों को हैरानी में डाल दिया है और इसकी वजह भी वाजिब है। लेकिन लोग उनकी बात सुनकर बौखला गए हैं और कहा है कि 'ये आदमी कुछ भी बोलता है।'

अन्नू कपूर ने बिना समय गंवाए तमन्ना भाटिया के उस वायरल बयान का मजाक उड़ाया जिसमें उन्होंने कहा था कि माएं बच्चों को सुलाने के लिए गाना गाती हैं। अपनी खास जुबान पर आते हुए उन्होंने पलटवार किया और शुभांकर मिश्रा के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, 'आहा, माशाअल्लाह क्या दूधिया बदन है। बच्चे कितने साल के हो जाते हैं? 70 साल का बच्चा भी सो सकता है! अंग्रेजी में कहते हैं वह 70 साल का है। मैं 70 साल का बच्चा हूं, कोई 11 साल का बूढ़ा भी हो सकता है। तो फिर कौन सोता है? ये कैसे पता!'

अन्नू कपूर ने उड़ाया मजाक

बिना एक पल भी गंवाए अन्नू कपूर तमन्ना भाटिया के लिए मजाकिया तारीफ करते हुए कहते हैं, 'बहन तमन्ना भाटिया, अपने गाने से, या अपने दूधिया चेहरे और बदन से, अगर वो हमारे बच्चों को मीठी नींद सुला रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है यार... यह इस देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि हमारे बच्चे मीठी और सेहतमंद नींद सोएं।'

अन्नू कपूर का तमन्ना पर कमेंट

यह ऐसा कमेंट है जिससे सिर्फ दिग्गज अन्नू कपूर ही बच निकल सकते हैं। जब लगता है कि उनकी बात खत्म हो गई है तो अन्नू कपूर एक प्यारी सी बात और कहते हैं, 'अगर उनकी कोई और इच्छाएं हैं, तो ईश्वर उन्हें (तमन्ना) क्षमता प्रदान करें, उन्हें आशीर्वाद दें ताकि वह उनकी इच्छाएं पूरी कर सकें। यह उनके लिए मेरा आशीर्वाद है।'

ऐश्वर्या पेट के ळइ के कारण कंसीव नहीं कर

अमिताभ बच्चन अपने परिवार के लिए अक्सर स्टैंड लेते हैं। कोई कुछ भी कहे, वह उसे पलटकर जवाब देते हैं। 15 साल पहले 2010 में एक खबर फैली थी कि ऐश्वर्या पेट के टीबी के कारण कंसीव नहीं कर पा रही हैं। इस पर एक्टर ने जमकर सुनाया था।

अमिताभ ने दिया था जवाब

बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन और उनका पूरा परिवार अफवाहों को जरा भी बर्दाश्त नहीं करता। कई बार वो लीगल एक्शन लेने पर मजबूर हो जाते हैं। एक बार ऐश्वर्या राय के बारे में खबर आई थी कि वह मां नहीं बन सकतीं। क्योंकि वह पेट की टीबी के कारण कंसीव नहीं कर पा रही हैं। इस पर पूरा परिवार तिलमिला गया था। बिग बी ने तो फौरन इस पर रिएक्ट किया था और गुस्सा जाहिर किया था। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में ऐश्वर्या राय के प्रेग्नेंसी को लेकर साल 2010 में फैलाई गई झूठी खबर की निंदा की थी और इसे झूठा, मनगढ़ंत और असंवेदनशील बताया था। उन्होंने लिखा था, 'मैं आज आपको बहुत दर्द और नफरत के साथ लिख रहा हूं। ये आर्टिकल पूरी तरह से फेक है। पूरी तरह से मनगढ़ंत, निराधार, असंवेदनशील और पत्रकारिता के सबसे निम्न स्तर का है।'

सिकंदर डायरेक्टर ने सलमान पर लगाए लेट आने के आरोप:एक्टर बोले- उनकी अगली फिल्म में हीरो 6 बजे आता था, वो सिकंदर से बड़ी फ्लॉप

सलमान खान ने हाल ही में सिकंदर के डायरेक्टर एआर मुरुगादॉस के उस बयान पर जवाब दिया है, जिसमें उन पर सेट पर देरी से आने के आरोप लगाए गए थे। सलमान ने कहा कि अगर उनके लेट आने से फिल्म फ्लॉप हुई तो उनकी अगली फिल्म उससे भी बड़ी फ्लॉप क्यों थी।

बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान के साथ स्टैंड अप कॉमेडियन रवि गुप्ता ने मंच शेयर किया। इस दौरान रवि गुप्ता ने पूछा कि उन्हें कौन सी फिल्में करने पर लगा कि ये क्या कर दिया। जवाब में सलमान ने निश्चय और सूर्यवंशम फिल्मों का नाम लिया। जब रवि ने हालिया फिल्म के बारे में पूछा तो सलमान ने कहा, 'नई में से कोई नहीं है। लोग कहते हैं सिकंदर, पर मैं नहीं मानता। उसका प्लॉट पहुंच अच्छा था।'

आगे सलमान ने सिकंदर डायरेक्टर एआर मुरुगादॉस के लेट आने वाले आरोप पर तंस कसते हुए कहा, 'लेकिन क्या है न मैं सेट पर रात के 9 बजे पहुंचता था, तो उसमें गड़बड़ हो गई। मेरी पसलियां टूटी थी, जो हमारे डायरेक्टर (एआर मुरुगादॉस) साहब हैं उन्होंने ये कहा। लेकिन उनकी पिक्चर (मधरासी) अभी एक रिलीज हुई है, जिसमें एक्टर 6 बजे पहुंचता था।'

'तो पहले तो ये पिक्चर थी मुरुगादॉस और साजिद नाडियाडवाला की। उसके बाद साजिद पहले कल्टी, मुरुगादॉस वापस से हट गया, वहां से सीधा साउथ में पिक्चर की। मधरासी करके पिक्चर उन्होंने डायरेक्ट की है, जो कि रिलीज हुई, बहुत बड़ी फिल्म है और उतनी ही बड़ी, सिकंदर से भी बड़ी ब्लॉकबस्टर (फ्लॉप)।' ये कहते हुए सलमान सर्कास्टिक स्माइल के साथ तंज करते हैं।

बता दें कि बीते महीने यूट्यूब चैनल वलाइपेचु वॉयस के साथ बातचीत के दौरान मुरुगादॉस ने कहा था, ह्लकिसी बड़े स्टार के साथ शूट करना आसान नहीं होता। दिन के सीन भी हमें रात में शूट करने पड़ते थे क्योंकि वह (सलमान) रात 8 बजे ही सेट पर आते थे। हम लोग सुबह से काम शुरू करने के आदी हैं,

बॉबी ने 26 साल बाद अपनी हीरोइन को देख कसकर लगाया गले, देखती रही साड़ी पहन पीछे खड़ी बीवी, महफिल लूट गई प्रीति

सोशल मीडिया पर इस समय मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी की तस्वीरें ही छाई हुई हैं। जिसमें सारा ही बॉलीवुड ही एक छत के नीचे आ पहुंचा, लेकिन यहां बॉबी देओल का बीबी के सामने ही अपनी 26 साल पुरानी हीरोइन को गले लगाने वाला अंदाज वायरल हो गया। जहां सभी देसी रंग में रंगकर दिवाली का जश्न मनाने पहुंचे थे।

मनीष मल्होत्रा बी- टाउन की बेस्ट दिवाली पार्टी आयोजित करने के लिए जाने जाते हैं। हर साल उनकी पार्टी का इंतजार जितना सितारों को रहता है, उतना ही फैंस को भी होता है और होगा भी क्यों नहीं, एक शाम में ही इतने सितारों का देसी रूप जो देखने को मिल जाता है। तभी तो 12 अक्टूबर की शाम फैशन डिजाइनर के घर हुई पार्टी की फोटोज से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। लेकिन, यहां सारे सितारों के देसी रूप के बीच एक 26 साल पुरानी फिल्मी जोड़ी सारी लाइमलाइट लूट ले गई।

यहां हम बॉबी देओल और प्रीति जिंटा की बात कर रहे हैं, जो जब 1998 में फिल्म 'सोल्जर' में साथ दिखी, तो हर कोई उनकी केमिस्ट्री का फैन बन गया था। वहीं, अब एक बार फिर दोनों को साथ देखकर फैंस का दिल खुश हो गया। जहां सूट पहनकर आई प्रीति की नजर जैसे ही बॉबी पर गई, तो वह उनकी और दौड़ीं और एक्टर ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। वहीं, एक्टर की बीवी तान्या देओल दोनों को दूर खड़े होकर देखकर मुस्कारती दिखीं और यहां महफिल की जान डिंपल गर्ल का देसी चार्म बन गया।

प्रीति का देसी लुक लगा शानदार

सबसे पहले प्रीति के लुक पर नजर डालते हैं, जो यहां सूट पहनकर आईं। वाइट कलर के अनारकली पर सुनहरे लेस और गोटा पट्टी का काम हुआ है, जो इसे क्लासी बना रहा है। वहीं, फ्लोरल मोटिफ्स वाला पैटर्न भी उनके लुक में शाइन ले आया, जो वैसे तो बाकी सितारों के आउटफिट्स से थोड़ा कम चमचम वाला था, लेकिन फिर भी प्रीति अपने चार्म और क्लासी अंदाज से महफिल लूट गईं। अपने इस फुल स्लीव्स अनारकली को प्रीति ने मैचिंग पैंट्स के साथ पेयर किया। जिसके बॉर्डर को सुनहरी लेस से हाइलाइट किया है, तो साथ में उनका मैचिंग दुपट्टा भी बढ़िया लगा। जिसके सिर्फ बॉर्डर पर लेस लगी और इसे हसीना ने सादे तरीके से अपने कंधे पर एक साइड ओपन करके कैरी किया। जिसमें प्रीति का स्टाइल सबसे जुदा और स्टनिंग लगा।

हर स्टारकिड को सबकुछ असानी से नहीं... मोहनीश बहल की बेटी प्रनूतन ने सुनाई दो साल तक रिजेक्शन की आपबीती

प्रनूतन बहल ने 2019 में जहीर इकबाल के साथ 'नोटबुक' से डेब्यू किया था। यह फिल्म सलमान खान ने बनाई थी। मोहनीश बहल की बेटी और नूतन की पोती ने अब खुलासा किया है कि उन्होंने भी दो साल रिजेक्शन झेला है। वह कहती हैं कि हर स्टारकिड को सबकुछ आसानी से नहीं मिल जाता।

मोहनीश बहल की बेटी और दिग्गज एक्ट्रेस नूतन की पोती प्रनूतन बहल ने साल 2019 में 'नोटबुक' से बॉलीवुड डेब्यू किया था। सलमान खान के बैनर तले बनी इस फिल्म में जहीर इकबाल उनके हीरो थे। इसके बाद वह 2021 में 'हेलमेट' और 2024 में 'अमर प्रेम की प्रेम कहानी' में नजर आईं। प्रनूतन को उनकी डेब्यू फिल्म के लिए फिल्मफेयर नॉमिनेशन भी मिला था। एक ओर जहां इंडस्ट्री में स्टारकिड्स और नेपोटिज्म को लेकर बड़ी बहस चलती रहती है, वहीं 32 साल की प्रनूतन का कहना है कि

फिल्मी घराने से आने वाले हर बच्चे को सफलता और मौके थाली में सजाकर नहीं मिलते। हालिया इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कहा है कि डेब्यू से पहले उन्हें भी 2 साल तक रिजेक्शन झेलना पड़ा था।

'हिंदुस्तान टाइम्स' से बातचीत में प्रनूतन ने माना कि फिल्मी परिवार से होने के कारण उन्हें कुछ विशेषाधिकार मिले हैं। इस वजह से उन्हें फिल्मों के लिए बेहतर तैयारी करने का मौका मिला, लेकिन साथ ही, कुछ नुकसान भी उठाना पड़ा है।

'मुझे इंडस्ट्री में आने से पहले ही वॉर्निंग दी गई थी'

प्रनूतन ने कहा, 'क्योंकि मैं एक्टर्स से घिरी हुई रही हूं, इसलिए मेरे लिए यह समझना आसान हो गया कि यह इंडस्ट्री आसान नहीं है। आपको पता चलता है कि ऐसे भी दौर आ सकते हैं, जब आपके पास कोई काम नहीं होगा। मुझे इस तरह की वॉर्निंग (चेतावनी) दी गई थीं। बहुत से लोग जिनके माता-पिता इंडस्ट्री से नहीं हैं, उन्हें यह सब शुरूआत में समझ नहीं आता, और जाहिर तौर पर ऐसे में उनके लिए यह एक मुश्कलि इमोशनल जर्नी बन जाती है।'

'हर स्टारकिड को सबकुछ आसानी से नहीं मिल जाता'

हालांकि, प्रनूतन झट से आगे यह भी बताती हैं कि हर 'स्टारकिड्स' को इंडस्ट्री में आसानी से जगह नहीं मिलती है। वह कहती हैं, 'हर स्टारकिड को सब कुछ आसानी से नहीं मिल जाता, और मैं इसका जीता जागता सबूत हूं। ऐसा नहीं है कि मैं एक एक्टर की बेटी हूं, तो मुझे सब कुछ आसानी से मिल गया है या मेरा परिवार पीछे से फिल्मों के लिए पैसे दे रहा है।'

2016 से शुरू कर दिया था ऑडिशन देना

एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि भले ही उनकी पहली फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी, लेकिन उन्होंने 2016 से ही ऑडिशन देना शुरू कर दिया था। वह याद करते हुए बताती हैं, 'मुझे भी एक एक्टर होने के भावनात्मक उतार-चढ़ाव से जूझना पड़ा। हां, मेरे लिए यह सब एक झटका जैसा नहीं था। लेकिन, जाहिर है, यह एक इमोशनल जर्नी है। आपको बहुत सारे रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। मैंने 2016 में ऑडिशन शुरू किए और 2018 में मुझे मेरी पहली फिल्म मिली। उसके बाद भी, मैंने ऑडिशन देना जारी रखा। मैंने अभी तीन दिन पहले ही एक ऑडिशन दिया था।'

कैटी पेरी को किस करते दिखे जस्टिन ट्रूडो:कैलिफोर्निया में यॉट से फोटो वायरल, जुलाई में दोनों की डेटिंग की खबर आई थी

जस्टिन ट्रूडो ने जनवरी 2025 में ढट पद से इस्तीफा दे दिया था। वहीं, कैटी पेरी इस समय अपने लाइफटाइम वर्ल्ड टूर से ब्रेक पर हैं। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और अमेरिकी सिंगर कैटी पेरी की रोमांस की खबरें फिर से चर्चा में हैं। दोनों की यॉट पर कुछ इंटिमेट और क्लोज-अप तस्वीरें सामने आई हैं। ये फोटोज पिछले महीने की बताई जा रही हैं। डेली मेल के मुताबिक दोनों कैलिफोर्निया के सांता बारबरा तट पर कैटी की 24 मीटर लंबी यॉट पर थे।डेली मेल को मौके पर मौजूद एक शख्स ने बताया कि कैटी का यॉट पास के छोटे पब्लिक व्हेल-वॉचिंग बोट के पास आया और इसके बाद ट्रूडो और पेरी ने साथ में समय बिताया। शख्स ने कैटी के हाथ के टैटू देखकर पहचाना कि वह जस्टिन ट्रूडो के साथ थीं।

ट्रूडो ने साल 2023 में अपनी पत्नी सोफी से 18 साल पुरानी शादी खत्म कर दी थी। वहीं, कैटी पेरी का इस साल एक्टर ऑरलैंडो ब्लूम के साथ ब्रेकअप हुआ था। पेरी के ब्रेकअप के कुछ दिन बाद से ही उनकी ट्रूडो के साथ अफेयर की खबरें सामने आईं।इसी साल जुलाई में पेरी और ट्रूडो को एक साथ डिनर करते देखा गया था। ळटे की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की मुलाकात कनाडा के मॉन्ट्रियल में रेस्त्रां ले वायलोन में हुई थी।इस मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। वीडियो में पेरी और ट्रूडो एक ही टेबल पर आमने-सामने बैठे बातचीत करते दिख रहे थे।

सुरक्षा में कई गार्ड भी तैनात थे

यह डिनर एक प्राइवेट डेट जैसा लग रहा था, लेकिन दोनों अकेले नहीं थे। उनके साथ कई सुरक्षा गार्ड भी मौजूद थे, जो उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। सुरक्षाकर्मी पास की सीटों पर बैठे थे और शीशे की दीवार के जरिए निगरानी कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक पैरी और ट्रूडो ने रेस्त्रां में कई डिशेज ली थीं। इनमें लॉब्स्टर भी शामिल था, लेकिन दोनों ने कोई एल्कोहॉलिक ड्रिंक नहीं ली। डिनर के बाद रेस्त्रां के हेड शेफ खुद दोनों से मिलने आए और उनका स्वागत किया। खाना खत्म होने के बाद पैरी और ट्रूडो दोनों ने किचन जाकर स्टाफ को पर्सनली थैंक्स कहा था।कैटी पेरी और एक्टर ऑरलैंडो ब्लूम का रिश्ता 2016 में गोल्डन ग्लोब्स की एक आफ्टर पार्टी में शुरू हुआ था। दोनों के बीच जल्द ही नजदीकियां बढ़ीं और यह रिश्ता मीडिया की सुर्खियों में आ गया।2017 में उनका कुछ समय के लिए ब्रेकअप हुआ, लेकिन 2018 में उन्होंने फिर से एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया। इसके बाद 2019 में वेलेंटाइन्स डे के मौके पर दोनों ने सगाई कर ली।

53 की कुंवारी तब्बू बन गई महारानी, हरे अनारकली में दिखाया शाही रौब, रैंप पर अदाएं देख फिसला दीवानों का दिल

तब्बू न सिर्फ अपनी कमाल की एक्टिंग के लिए लोगों के बीच पहचानी जाती हैं, बल्कि उनका स्टाइल भी कमाल का है। हसीना जहां जाती हैं उनका अंदाज छा जाता है और अब तो हरे रंग के कपड़ों में महारानी की तरह सज-संवरकर वह शाही रौब दिखा गईं। इंडस्ट्री में ऐसी कई एक्ट्रेस हैं, जो 50 का पड़ाव पार करने के बाद भी अपने लुक्स से दिल जीत लेती हैं। उनका स्टाइल इतना कमाल का है कि आज भी उनके आगे नए जमाने के सितारे फीके पड़ जाए और इस लिस्ट में तब्बू भी शुमार हैं। हसीना भले ही अब 53 साल की हो गई हैं और अभी तक कुंवारी हैं, लेकिन स्टाइल के मामले में वह अभी भी किसी से पीछे नहीं रहतीं। तभी तो अब उनका महारानी वाला लुक सोशल मीडिया पर छा गया है।

दरअसल, तब्बू नई दिल्ली में चल रहे लैक्मे फैशन वीक में पहुंचीं। जहां जैसे ही उन्होंने रैंप पर एंट्री ली, तो हर कोई उनके शाही ठाठ- बाट देखता रह गया। वह इतने ग्रेस और कॉन्फिडेंस के साथ अपना जलवा बिखेर गईं कि किसी और पर ध्यान ही नहीं गया। अब आप खुद ही उनके लुक पर नजर डाल लीजिए।

'नूर' कलेक्शन में नूर की तरह चमकीं तब्बू

हमेशा ही अपने देसी लुक्स से दिल जीतने वाली तब्बू फैशन वीक में क३१ँ के 'नूर' कलेक्शन के लिए शो स्टॉपर बनीं। जहां वह उनके लेटेस्ट कलेक्शन से ही गहरे हरे रंग का अनारकली पहनकर सामने आईं और एकदम महारानी वाली वाइब्स दे गईं। गहनों से लेकर एक्ट्रेस के चेहरे पर नजर आ रहे तेज तक, सब कुछ उनके लुक की ब्यूटी को बढ़ा रहा है। तब्बू के अनारकली को इंटीक्रेट एम्ब्रॉयडरी और शिमरी जरी डीटेल्स से सजाया गया है। जिसकी स्वीटहार्ट नेकलाइन और स्लीव्स फुल हैं, तो ग्रीन कलर के इसमें दो डार्क शेड्स का कमाल का कॉम्बिनेशन देखने को मिला। जहां चोली वाले एरिया को हैवी वर्क से सजाया, तो उसके बॉर्डर को किरण लेस से हाइलाइट किया। जिसका कंधे पर आता डिजाइन शानदार लगा। वहीं, स्लीव्स को चोली के मुकाबले काम थोड़ा काम है। अनारकली के साथ तब्बू का कलीदार घाघरा भी बेहद क्लासी लगा। जिसकी एक कली को हल्का तो दूसरे को गहरे हरे रंग का रखा और फिर उसे सेक्विन सितारों से बड़ी खूबसूरती से जाली वर्क बनाकर सजाया। जिसके बीच में बना फूल जैसा पैटर्न भी शानदार लगा। हर कली को डिफाइन करने के लिए सुनहरे सितारों से डिजाइन बनाया। वहीं, इस लहंगा अनारकली के साथ ही सिल्वर स्कर्ट अटैच है,

प्रदेश स्तरीय रेड क्रॉस बैठक में सूरजपुर की सशक्त भागीदारी, मानव सेवा के नए अध्याय की शुरूआत

*** राज्य चेयरमैन का जल्द होगा जिला दौरा, जनसेवा को और प्रभावी बनाने पर बनी कार्ययोजना**

सूरजपुर, 03 अगस्त 2026, द शूटर।मुसीबत के समय किसी अनजान चेहरे के आंसू पोंछने का साहस ही इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है। यही भावना रेड क्रॉस जैसी संस्था को दुनिया भर में अलग पहचान देती है। जरूरतमंदों तक समय पर मदद पहुंचाने और समाज में सेवा की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से राजधानी रायपुर स्थित रेड क्रॉस भवन में इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी की प्रदेश स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलों से पहुंचे प्रतिनिधियों ने न केवल अपने-अपने क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया, बल्कि आने वाले समय में मानव सेवा के दायरे को और व्यापक बनाने पर भी गंभीर मंथन किया।

बैठक की अध्यक्षता राज्य चेयरमैन तोमन साहू ने की। इस दौरान राज्य जनरल सेक्रेटरी डॉ. रूपल पुरोहित, प्रदेश पदाधिकारी, राष्ट्रीय एवं प्रदेश प्रतिनिधि प्रबंध समिति के सदस्य, सभी जिलों के जिला चेयरमैन, जिला सचिव और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित रहे। सभी जिलों ने अपने-अपने यहां संचालित राहत कार्यों, रक्तदान अभियान, स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक गतिविधियों और संगठन की प्रगति का विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। साथ ही भविष्य में रेड क्रॉस की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

पहली बार प्रदेश स्तर पर प्रभावी रूप से गूंजा सूरजपुर का नाम

इस बैठक की सबसे खास उपलब्धि सूरजपुर जिले की सशक्त उपस्थिति रही। पहली बार जिले का प्रतिनिधित्व जिला चेयरमैन बाबूलाल अग्रवाल तथा जिला सचिव एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. कपिल देव पैकरा ने किया। दोनों ने

जिले में संचालित गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं का विस्तार से प्रस्तुतीकरण किया। प्रदेश नेतृत्व ने सूरजपुर की सक्रियता की सराहना करते हुए कहा कि आने वाले समय में यहां रेड क्रॉस की गतिविधियों को और व्यापक स्वरूप दिया जाएगा।

राज्य चेयरमैन का जल्द होगा सूरजपुर दौरा

बैठक के दौरान यह जानकारी भी साझा की गई कि राज्य चेयरमैन तोमन साहू शीघ्र ही सूरजपुर का दौरा करेंगे। प्रस्तावित दौरे के दौरान वे जिला शाखा की कार्यप्रणाली की समीक्षा करेंगे, स्थानीय आवश्यकताओं का जायजा लेंगे और जनहित से जुड़े नए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरे के बाद जिले में रेड क्रॉस की गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

मानव सेवा में उदासीनता बर्दाश्त नहीं

बैठक में कई जिलों के प्रतिनिधियों ने यह मुद्दा उठाया कि कुछ स्थानों पर संबंधित अधिकारियों द्वारा रेड क्रॉस की गतिविधियों में अपेक्षित सहयोग नहीं दिया जा रहा है। इस पर प्रदेश नेतृत्व ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मानव सेवा से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी संबंधित अधिकारियों से सक्रिय सहयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

कलेक्टरों की विशेष बैठक भी होगी

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों की जल्द ही विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। चूंकि प्रत्येक जिले के कलेक्टर रेड क्रॉस सोसायटी की जिला शाखा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, इसलिए जिला स्तर पर बेहतर समन्वय और जनसेवा कार्यक्रमों को गति देने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

सूरजपुर में बनेगी नई प्रबंधन टीम

सूरजपुर जिला शाखा की नई प्रबंधन टीम के गठन पर भी सहमति बनी। नई टीम के गठन के बाद रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य परीक्षण, प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण, आपदा राहत, जनजागरूकता अभियान और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग जिम्मेदारियां तय की जाएंगी, ताकि संगठन की कार्यप्रणाली अधिक व्यवस्थित और परिणामकारी बन सके।

सेवा का दायरा बढ़ाने का संकल्प

रायपुर में आयोजित यह बैठक केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं रही, बल्कि मानव सेवा के संकल्प को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण मंच साबित हुई। सूरजपुर की प्रभावी भागीदारी, राज्य चेयरमैन के प्रस्तावित दौरे, नई प्रबंधन टीम के गठन और प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करने जैसे निर्णय यह संकेत देते हैं कि आने वाले दिनों में जिले में रेड क्रॉस की गतिविधियां और अधिक सक्रिय, संगठित तथा जनहितकारी स्वरूप में दिखाई देंगी। जब सेवा का उद्देश्य केवल दायित्व नहीं बल्कि संवेदना बन जाता है, तब समाज में बदलाव की शुरूआत अपने आप होने लगती है।

राशन व्यवस्था पर फूटा लोगों का गुस्सा, कांग्रेस ने खाद्य अधिकारी को सौंपा ज्ञापन

*** राशन दुकानों के अनियमित संचालन, एपीएल को चावल और अंत्योदय हितग्राहियों को चार माह से शक्कर नहीं मिलने का उठाया मुद्दा**

अम्बिकापुर, 03 अगस्त 2026, द शूटर। शहर के कई वार्डों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बदहाल व्यवस्था को लेकर सोमवार को कांग्रेस नेताओं ने जिला खाद्य अधिकारी का दरवाजा खटखटाया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद मंडल के अध्यक्ष निकी खान के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने राशन वितरण में अनियमितता, राशन दुकानों के समय पर नहीं खुलने और हितग्राहियों को हो रही परेशानियों का विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि कई राशन दुकानें नियमित रूप से नहीं खुल रही हैं। निर्धारित समय पर दुकानें बंद रहने से आम उपभोक्ताओं, खासकर गरीब और मजदूर परिवारों को बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कई बार पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी लोग खाली हाथ लौटने को मजबूर हो जाते हैं।कांग्रेस नेताओं ने खाद्य अधिकारी को बताया कि एपीएल कार्डधारकों को लंबे समय से चावल का वितरण नहीं किया जा रहा है। वहीं अंत्योदय कार्डधारकों को पिछले चार महीने से शक्कर नहीं मिलने के कारण उनमें भारी नाराजगी है। प्रतिनिधिमंडल ने इन दोनों समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने की मांग की।बैठक के दौरान बायोमैट्रिक सत्यापन से जुड़ी समस्या भी प्रमुखता से उठाई गई। नेताओं ने कहा कि पहले ओटीपी के माध्यम से भी राशन वितरण की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन अब केवल बायोमैट्रिक मिलान के आधार पर राशन दिया जा रहा है। इससे कई बुजुर्गों और मेहनतकश लोगों के अंगूठे का मिलान नहीं हो पाता, जिसके कारण वे पात्र होने के बावजूद राशन से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने की भी मांग की ताकि किसी जरूरतमंद का हक न छिने।

जिला खाद्य अधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल की बात गंभीरता से सुनते हुए सभी शिकायतों की जांच कराने और जल्द आवश्यक कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया।ज्ञापन सौंपने वालों में शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह धंजल, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम, पार्षद मोहम्मद हसन, मोहम्मद बाबर, मंडल अध्यक्ष चंद्रप्रकाश सिंह, सौरभ फिलिप, काजू खान, विजय सोनी, शमसु अंसारी, अब्दुल वाहिद, अजहर मंसूरी, मोहम्मद औरंगजेब सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

रात्रि की खामोशी में वन विभाग का शिकंजा, पिकअप सहित सागौन की अवैध लकड़ी जब्त

*** छिंदिया जंगल में घेराबंदी कर कार्रवाई, सागौन के 4 लट्ठे बरामद, वाहन समेत लाखों की संपत्ति जब्त; वन अपराध प्रकरण दर्ज**

रामानुजनगर, 03 अगस्त 2026, द शूटर। जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सांसों का आधार हैं। इन्हीं हरित धरोहरों को बचाने की जिम्मेदारी निभाते हुए वन विभाग ने रात्रि गश्त के दौरान अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सागौन की इमारती लकड़ी से भरी एक पिकअप वाहन को पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान तीन लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

जानकारी के अनुसार, वन परिक्षेत्र रामानुजनगर के छिंदिया बीट में वन विभाग को 2 अगस्त की रात अवैध लकड़ी परिवहन की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही विशेष टीम गठित कर जंगल क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई। सोमवार तड़के लगभग 3 बजे गश्त के दौरान छिंदिया जंगल से निकल रही एक संदिग्ध सफेद रंग की पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 15 एसी 1294 को घेराबंदी कर रोक लिया गया।

जांच में वाहन से सागौन प्रजाति के 4 नग इमारती लट्ठे बरामद हुए। माप लेने पर लकड़ी की कुल मात्रा 0.580 घनमीटर पाई गई, जिसकी अनुमानित कीमत 43 हजार 826 रुपये आंकी गई है। वहीं जब्त पिकअप वाहन की कीमत लगभग 2 लाख रुपये बताई गई है।वाहन चालक ने पूछताछ में अपना नाम सूरज, निवासी सुमेरपुर बताया। वन विभाग ने लकड़ी और वाहन को जब्त कर रामानुजनगर वन परिक्षेत्र कार्यालय लाया तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की संबंधित धाराओं के तहत वन अपराध प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले में फरार अन्य आरोपियों की पहचान कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।वन परिक्षेत्र अधिकारी पूजा यादव ने बताया कि क्षेत्र में अवैध कटाई और लकड़ी परिवहन के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जंगलों की संपदा को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि यदि कहीं भी वन अपराध की जानकारी मिले तो उसकी सूचना तत्काल वन विभाग को दें, ताकि प्राकृतिक धरोहरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

बैकुण्ठपुर के वार्ड 09 में नाली निर्माण पर उठे सवाल, रात में मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में हो रही स्लैब ढलाई

बैकुण्ठपुर। द शूटर। नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर के वार्ड क्रमांक 09 में चल रहे नाली निर्माण कार्य को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार की मनमानी चरम पर है और कई शिकायतों के बावजूद कार्य में सुधार नहीं किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों से लेकर अंबिकापुर स्थित कार्यालय तक की जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी निर्माण कार्य में कथित अनियमितताएं लगातार जारी हैं।

वार्डवासियों के अनुसार नाली के ऊपर स्लैब ढलाई का कार्य रात के समय मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में कराया जा रहा है, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर संदेह उत्पन्न हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्रकार रात में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के बिना ढलाई किया जाना तकनीकी मानकों के अनुरूप नहीं माना जा सकता। आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदार द्वारा आवागमन का रास्ता भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों को प्रतिदिन भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों, बुजुर्गों और दोपहिया वाहन चालकों के लिए रास्ता जोखिमभरा बन गया है। स्थानीय नागरिकों का यह भी कहना है कि नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी निर्माण स्थल पर नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहते, जबकि गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी अधिकारियों की निगरानी आवश्यक होती है। लोगों का कहना है कि जब एक ही निर्माण कार्य को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं, तब उसी ठेकेदार को अन्य वार्डों में दिए गए तीन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर भी चिंता स्वाभाविक है। निर्माण स्थल पर कार्यरत श्रमिकों के श्रम पंजीयन नहीं होने का मुद्दा भी पहले समाचारों में प्रकाशित हो चुका है। इसके बावजूद अब तक संबंधित विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले तीन दिनों से नाली की नियमित तराई (क्योरिंग) भी नहीं की जा रही, जबकि निर्माण मानकों के अनुसार प्रतिदिन तराई किया जाना आवश्यक होता है, ताकि कंक्रीट को पर्याप्त मजबूती मिल सके।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि निर्माण की नींव और गुणवत्ता से समझौता किया जाएगा तो भविष्य में संरचना की मजबूती पर भी सवाल उठेंगे। लोगों ने जिला प्रशासन से पूरे निर्माण कार्य की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराने, गुणवत्ता परीक्षण कराने तथा दोषी पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।

महंगी बिजली और स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस का बिगुल, रामानुजनगर में चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति तैयार

*** गांव-गांव जनजागरण अभियान चलाने का निर्णय, बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने पर जोर**

रामानुजनगर, 03 अगस्त 2026, द शूटर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार रामानुजनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को आयोजित की गई। बैठक में प्रदेशभर में महंगी बिजली, स्मार्ट मीटर और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रस्तावित चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि बढ़ती बिजली दरों और स्मार्ट मीटर को लेकर आम लोगों में असंतोष लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करेगी।बैठक में वक्ताओं ने कहा कि बिजली की बढ़ी हुई दरों का सीधा असर किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है। वहीं स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को लेकर भी उपभोक्ताओं की ओर से लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसे में जनता की समस्याओं को सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए व्यापक जनजागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया।

गांव-गांव पहुंचेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता

बैठक में तय किया गया कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता गांव-गांव और वार्ड-वार्ड जाकर लोगों से संपर्क करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और चरणबद्ध तरीके से ज्ञापन, धरना-प्रदर्शन तथा अन्य लोकतांत्रिक आंदोलनों के माध्यम से उनकी आवाज शासन तक पहुंचाएंगे।

बैठक में पारित हुए प्रमुख प्रस्ताव

बैठक में सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। इनमें प्रदेश में बढ़ाई गई बिजली दरों को तत्काल वापस लेने, स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर रोक लगाने तथा जहां स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं वहां पूर्व व्यवस्था बहाल करने की मांग शामिल रही। इसके साथ ही कांग्रेस सरकार के समय लागू 400 यूनिट तक आधा बिजली बिल योजना को फिर से शुरू करने

तथा बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी निराकरण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई।

संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने पर जोर

बैठक में केवल आंदोलन की रणनीति ही नहीं, बल्कि संगठनात्मक मजबूती पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने, विभिन्न मंडलों एवं प्रकोष्ठों में आवश्यक जिम्मेदारियां तय करने और कार्यकताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया।ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र साहू ने कहा कि कांग्रेस हमेशा जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी पूरी मजबूती के साथ लड़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि महंगी बिजली और स्मार्ट मीटर जैसे मुद्दों से आम लोग परेशान हैं, इसलिए पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से उनकी आवाज बुलंद करेगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के महामंत्री चंद्रदत्त दुबे ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन किया जाएगा। प्रत्येक गांव और वार्ड में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और आंदोलन को सफल बनाने के लिए कार्यकताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।

आंदोलन को सफल बनाने का लिया संकल्प

बैठक के अंत में उपस्थित सभी पदाधिकारियों और कार्यकताओं ने संकल्प लिया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रस्तावित चरणबद्ध आंदोलन को पूरी ताकत के साथ सफल बनाया जाएगा। साथ ही महंगी बिजली, स्मार्ट मीटर और अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच लगातार सक्रिय रहकर लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया।बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष शशि सिंह, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र साहू, बिहारी कुलदीप, महामंत्री चंद्रदत्त दुबे, गोपाल शर्मा, आनंद कुँवर, विमला सिंह, समरथ प्रजापति, विजय साहू, हमेंद्र साहू, अविनाश यादव, बालमुकुंद दास, राजेंद्र हितकर, राम साहू, महेश सिंह, विनय दुबे, अविनाश साहू, भोला गुप्ता, खुशी, अरबीना, तीरथ सिंह, राजेश सोनी, संतोष साहू, मिथुन चक्रधारी, वागिशा मानिकपुरी, परमेश्वर सिंह, विनय महंत, मिलन दास, जय सिंह, कृष्णा साहू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में 24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस की त्वरित कार्रवाई

*** मासूम की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को नहीं मिलेगी राहत, पोक्सो एक्ट के तहत भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में**

अम्बिकापुर, 03 अगस्त 2026, द शूटर। समाज में बच्चों की सुरक्षा और सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में नाबालिगों के साथ होने वाले अपराध न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि सामाजिक संवेदनाओं को भी गहरी चोट पहुंचाते हैं। सरगुजा पुलिस ने ऐसे ही एक गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 2 अगस्त की है। नाबालिग पीड़िता ने थाना कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि ग्राम करम्हा निवासी गौतम राम उर्फ सटेल ने उसे अकेला पाकर उसकी लज्जा भंग करने के उद्देश्य से जबरन छेड़छाड़ की। किसी तरह पीड़िता वहां से बचकर निकली और घर पहुंचकर पूरी घटना अपने परिजनों को बताई। इसके बाद परिजनों के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई।पीड़िता की शिकायत के आधार पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 537/26 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74, 75(2), 76 तथा पोक्सो एक्ट की धारा 8 एवं 12 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना कोतवाली पुलिस ने तत्काल जांच प्रारंभ की। घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही आरोपी की तलाश तेज कर दी गई। पुलिस टीम के लगातार प्रयासों के बाद आरोपी गौतम राम उर्फ सटेल (40 वर्ष), निवासी ग्राम करम्हा, थाना अम्बिकापुर को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने घटना स्वीकार कर ली। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकांत सिन्हा, प्रशिक्षु उप निरीक्षक आशी झा, महिला प्रधान आरक्षक राधा यादव, प्रधान आरक्षक सूरज राय तथा आरक्षक परवेज फिरदोसी की सक्रिय भूमिका रही।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नाबालिगों से जुड़े अपराधों के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि समाज में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और अपराधियों में कानून का भय बना रहे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक- रूपेश दुबे द्वारा आर्यन ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस, पॉवर हाउस रोड नमना कला अम्बिकापुर, सरगुजा, छ0ग0 से मुद्रित एवं मेन रोड प्रतापपुर, खोरमा, जिला- सूरजपुर, छ0ग0 से प्रकाशित। संपादक- प्रवीण दुबे* (* समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। फोन- 07777271215